वर्ष 12 • अंक 261 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 20 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

सरकारी कदम से दलहन कीमतों पर लगेगी लगाम

निर्मला सीतारमण पृष्ठ 4

उद्यमियों ने वित्त मंत्री से मांगी कारोबार की आजादी

डॉलर रु. 71.00 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 79.10 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37877 ▼ 82 रुपये | सेंसेक्स 41673.90 ▲ 115.40 | निफ्टी 12259.70 ▲ 38.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12269.00 ▲ 09.30 | ब्रेंट क्रूड 67.80 डॉलर (अपरिवर्तित)

एक नज़र

रेटिंग घटाने के बाद भी चढ़े येस बैंक के शेयर

रेटिंग एजेंसियों ने रकम जुटाने की योजना को लेकर अनिश्चितता के बीच निजी क्षेत्र के ऋणदाता येस बैंक की रेटिंग घटा दी। हालांकि इसके बावजूद बैंक के शेयर में गुरुवार को खासी तेजी देखी गई। येस बैंक के शेयर ने कारोबार के दौरान 3 फीसदी की गिरावट से उबरते हुए अच्छी वापसी की और 7 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ। इससे पहले इंडिया रेटिंग्स और इक्रा ने उसकी रेटिंग घटा दी थी।

ईओआई पर जल्द फैसला करें जेट के ऋणदाता

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने जेट एयरवेज के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) को नए रुचि पत्र (ईओआई) मंगाने पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है। एनसीएलटी ने गुरुवार को कहा कि ठप खड़ी एयरलाइन के अधिग्रहण को लेकर नई रुचि सामने आई है, ऐसे में सीओसी को इस प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। एनसीएलटी के मुंबई पीठ ने कहा कि ऋणदाताओं की समिति को अभिरुचि पत्र जारी करने के बारे में जल्द फैसला करने का निर्देश दिया जाता है। कंपनी के समाधान पेशेवर आशीष छौछारिया ने ईओआई निकालने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है।

चीन ने हटाया अमेरिका की अतिरिक्त वस्तुओं से शुल्क

चीन ने गुरुवार को अमेरिका के उन रसायनों की सूची जारी की जिनपर आयात शुल्क की छूट होगी। दोनों देशों में करीब एक सप्ताह पहले व्यापार करार पर सहमति बनी थी, जिससे पिछले कई महीने से जारी विवाद नरम पड़ा है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को प्रथम चरण के करार की घोषणा की थी, जिसके तहत कुछ वस्तुओं से शुल्क में कटौती की जाएगी। चीन के सीमा शुल्क आयोग ने कहा कि यह छूट 26 दिसंबर से अगले साल 25 दिसंबर तक जारी रहेगी।

केंद्र ने राशन कार्ड का मानक प्रारूप पेश किया

केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है। राज्यों से कहा गया है कि नया राशन कार्ड जारी करते हुए वे इसी प्रारूप को अपनाएं। पूरे देश में एक जैसे राशन कार्ड जारी करने की पहल के तहत वर्तमान में छह राज्यों में परीक्षण योजना के तौर पर इस पर अमल किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस योजना को1 जून, 2020 से पूरे देश में लागू करना चाहती है। एक देश, एक राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद कोई भी कार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेगा।

शिविंदर की हिरासत 26 दिसंबर तक के लिए बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के धन की कथित हेराफेरी से संबंधित धनशोधन मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत की अवधि गुरुवार को 26 दिसंबर तक बढ़ा दी। ईडी ने पूछताछ के लिए सिंह को सात दिन के लिए हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था। जांच एजेंसी ने सिंह की सात दिन की हिरासत मांगते हुए कहा कि उनका सामना कुछ मुखौटा कंपनियों के निदेशकों से कराना है, जिन्हें जांच एजेंसी ने तलब किया है।

व्यापार गोष्ठी

सहकारी बैंकों की व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या जीएसटी क्रेडिट पर बंदिश से बढ़ेगी उद्योग की मुश्किल

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या एनसीएलटी के आदेश से टाटा समूह की फर्मों पर पड़ेगा असर?	हां	66.67%
	नहीं	33.33%

टाटा संस का दर्जा बदलने पर कंपनी पंजीयक से मांगा जा सकता है जवाब

प्राइवेट लिमिटेड दर्जे पर सवाल

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली/मुंबई, 19 दिसंबर

कंपनी मामलों का मंत्रालय मुंबई के कंपनी पंजीयक से पूछ सकता है कि टाटा सन्स को पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने की अनुमति देने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह बताया।

अधिकारी ने कहा, 'यदि मुख्य डेटा में किसी भी कंपनी का दर्जा बदलने की जरूरत पड़ती है तो यह काम कंपनी पंजीयक के पास छोटी सी प्रक्रिया का पालन कर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकता।' जिस समय टाटा सन्स ने अपना दर्जा बदलने की दरख्वास्त की थी, उस समय कंपनी कानून की धारा 14 के अनुसार सबसे पहले पंचाट की मंजूरी लेना जरूरी था। उसके बाद ही पंजीयक से कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए कहा जा सकता था।

लेकिन 2 नवंबर, 2018 से यह कानून बदल दिया गया और यह अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया। अधिकारी ने बताया, 'अब पंचाट के बजाय कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय इसकी मंजूरी दे सकता है।' साइरस मिस्त्री के वकील ने कहा था कि कंपनी का दर्जा बदलने का फैसला निदेशक मंडल ने जल्दबाजी में लिया था और इसमें 'कंपनी पंजीयक की मदद' ली गई थी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट ने इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया था और कंपनी पंजीयक से इसे रद्द करने को कहा था।

कानूनी मामलों के जानकारों ने कहा कि एनसीएलएटी के आदेश के बाद कंपनी पंजीयक, मुंबई को टाटा संस के निदेशकमंडल के किसी निर्णय का इंतजार किए बिना टाटा संस का दर्जा निजी कंपनी से बदलनकर सार्वजनिक कंपनी करना होगा। इसके अलावा कंपनी पंजीयक को टाटा संस से किसी तरह के कागजात की जरूरत नहीं है। जानकारों का कहना है कि टाटा संस को निजी कंपनी बनाने की पहल एनएसएलएटी ने पहले ही अवैध घोषित कर दी है, इसलिए अब किसी तरह के कागजात की आवश्यकता नहीं रह गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता एच पी रनीना ने कहा, 'आरओसी को निदेशक मंडल के किसी प्रस्ताव या कागजात का इंतजार नहीं करना चाहिए। टाटा संस ने जो किया उसे अनुचित ठहराया जा सकता है।'

सितंबर 2017 में टाटा संस ने स्वयं को सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में तब्दील कर लिया था। कंपनी के इस कदम से मिस्त्री परिवार और अन्य दूसरे अल्पांश शेयरधारकों के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचने की संभावनाएं सीमित हो गई थी।

इस बारे में पक्ष जानने के लिए टाटा संस के प्रवक्ता को ईमेल किया गया लेकिन जवाब नहीं आया। मिस्त्री के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में बदलने के बारे में टाटा संस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

एनसीएलएटी की टिप्पणी -

- टाटा संस को प्राइवेट कंपनी में बदलने का कंपनी पंजीयक का निर्णय अवैध
- कंपनी पंजीयक टाटा संस को तत्काल पब्लिक कंपनी के तौर पर दर्ज करेगा
- पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलाव पक्षपाती और टाटा संस के अल्पांश शेयरधारकों के हितों के खिलाफ है
- टाटा ट्रस्ट्स ने निदेशकों की नियुक्ति में पक्षपाती तरीके से काम किया

चारों श्रम संहिता अगले साल लागू!

सोमेश झा
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

- **सरकार के अनुसार एक ही तिथि से चारों संहिता लागू करने से आएगी एकरूपता**
- **वेतन पर श्रम संहिता बन चुका है कानून**
- **शेष तीन लोकसभा में पेश**
- **उद्योग जगत ने सरकार के कदम पर जताई नाराजगी**

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने सभी चार श्रम संहिता अगले साल एक ही तारीख से शुरू करने की योजना बना रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, 'सरकार का मानना है कि एक ही तिथि से चारों संहिता लागू करने से एकरूपता आएगी और इनका क्रियान्वयन भी सरलता से हो पाएगा।'

2019 में सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद राजग सरकार ने श्रम कानून में सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी है। वेतन पर श्रम संहिता पहले की कानून का शक्ल ले चुकी है और शेष तीन संहिता संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश की गई हैं। ये तीन संहिता क्रमशः औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम स्थिति से संबंधित हैं।

चारों संहिता के कानून बनने के बाद उद्योग को श्रम कानूनों के लिए एकल पंजीयन कराना होगा। फिलहाल उन्हें आठ अलग-अलग श्रम कानूनों से जुड़े पंजीयन कराने होते हैं। हालांकि अब सरकार एक ही तारीख से चारों संहिता लागू करना चाहती है, इसलिए वेतन अधिनियम संहिता, 2019 के क्रियान्वयन में कम से कम एक साल की देरी हो सकती है। हालांकि यह संहिता अगस्त में कानून बन चुकी है, लेकिन सरकार ने इनके क्रियान्वयन से जुड़ी अधिसूचना के लिए तिथि की घोषणा नहीं की है।

संहिता में मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में कामगारों को न्यूनतम पारिश्रमिक देने का प्रावधान है। न्यूनतम पारिश्रमिक के संबंध में पिछला कानून केवल कुछ ही उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों पर लागू होता था। वेतन अधिनियम संहिता लागू करने की तिथि की घोषणा बाद में होने का एक मतलब यह भी है कि उद्योग जगत को न्यूनतम वेतन में किसी तरह की संभावित बढ़ोतरी से भुगतान करने से कुछ राहत मिल सकती है।

अधिकारी ने कहा कि 36 श्रम कानूनों को चार संहिता के तहत लाने से वेतन, कर्मचारी, नियोक्ता, कार्य स्थल सहित दूसरे विषयों से जुड़ी मुख्य परिभाषाओं में तारतम्यता आएगी। हालांकि उद्योग जगत के कुछ लोगों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और कहा कि यह श्रम कानूनां में सुधार रोक देगी। महराता चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप भार्गव ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सभी अच्छे कदम एक ही साथ उठाए जाएं। भार्गव ने कहा कि सरकार इस मामले में दूरदर्शिता नहीं दिखा रही है, इसलिए वह उसके कदम से सहमत नहीं है।

जीएसटी क्रेडिट पर बंदिश से नकद प्रवाह पर होगा असर

उद्योग जगत को डर है कि जीएसटी परिषद द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के मद में भुगतान पर सख्ती से उनके लिए नकदी की किल्लत खड़ी हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने सही प्रारूप में अपलोड नहीं किए गए इनवॉइस पर भुगतान की जाने वाली राशि 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी है। परिषद ने गुरुवार को इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपने अपने आपूर्तिकर्ताओं को 1,000 रुपये कर के रूप में भुगतान किया है और अपने सारांश इनपुट-आउटपुट-फॉर्म जीएसटीआर 3बी पर इसका दावा आईटीसी के रूप में किया है, तब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके सभी आपूर्तिकर्ता सभी इनवॉइसों को अपने आपूर्ति पक्ष वाले रिटर्न- जीएसटीआर 2ए में अपलोड करें। पृष्ठ 4

देश भर में विरोध प्रदर्शन यूपी-बिहार में भड़की हिंसा

लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान पथराव में घायल पुलिसकर्मी। *पीटीआई*

बीएस संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में आज देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में हिंसा एवं आगजनी की घटनाएं देखी गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थिति को देखते हुए अपना दो दिवसीय गुजरात दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली लौट आए।

सुबह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन पर रोक के बाद भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और लगभग 20 मेट्रो स्टेशनों के गेट भी बंद किए गए, जिससे शहर में यातायात प्रभावित हुआ। ये स्टेशन देर शाम तक खोल दिए गए। मगर दिन में इंडिगो के चालक दल के सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर भयंकर जाम में फंसे रहे, जिस कारण कंपनी को 19 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और 16 अन्य उड़ानों में देर हुई। जिन यात्रियों की उड़ानें जाम में फंसने के कारण छूट गईं, उन्हें विस्तारा, एयर इंडिया और इंडिगो ने अन्य उड़ानों में जगह देने की पेशकश की।

दिन में विरोध प्रदर्शन की अगुआई कर रहे विपक्षी नेताओं डी राजा, सीताराम येचुरी, नीलोत्पल बसु, वृंदा करात, अजय माकन, संदीप दीक्षित और योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गांधीगीरी का सहारा लिया और सुरक्षा कर्मियों को गुलाब के फूल दिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने छात्रों और कार्यकर्ताओं से शांति बरतने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। वहां उपद्रवियों ने पथराव किया और वाहनों को आग लगा दी। शहर के अन्य कई हिस्सों में तनाव व्याप्त है। हसनगंज क्षेत्र में पथराव कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदेश के संभल जिले में दो सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। लखनऊ में हुई हिंसा में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधान भवन परिसर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से इसकी वसूली भी की जाएगी। उनकी संपत्ति को नीलाम कर वसूली की जाएगी।

बिहार की राजधानी पटना में वामपंथी छात्र संगठनों एआईएसएफ और आइसा से जुड़े कार्यकर्ता राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर बैठ गए जिससे सुबह करीब आधे घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। जन अधिकार पार्टी (जैप) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान वाहनों तथा बसों को नुकसान पहुंचाया।

बेंगलूरु में इतिहासकार रामचंद्र गुहा समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

आईपीएल की पिच पर कमिंस ने रच दिया इतिहास

विवेट सुजन पिंटो/भाषा
मुंबई/कोलकाता, 19 दिसंबर

पिछले दो साल से अपनी टीम के लिए खेल के तीनों प्रारूपों में शानदार गेंदबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने आज इतिहास रच दिया, जब वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने नीलामी में आज कमिंस को 15.5 करोड़ रुपये में खरीद लिया। कमिंस आईपीएल की नीलामी में युवराज सिंह के बाद अब तक के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। युवराज को 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था।

कोलकाता में आयोजित नीलामी में विभिन्न टीमों में खाली पड़ी 73 जगहें भरने के लिए कुल 332 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। नीलामी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने कहा कि नीलामी में सभी टीम मालिकों ने करीब 208 करोड़ रुपये खर्च किए।

कमिंस को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होड़ दिखी, लेकिन दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 15.50 करोड़ रुपये की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। कमिंस ने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी होने का बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स ने 2017 में 14.5 करोड़ रुपये में खरीदा था।

आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर ग्लेन मैक्सवेल के लिए दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब ने खासी दिलचस्पी दिखाई। पंजाब की टीम 10.75 करोड़ रुपये की बोली लगा कर उन्हें अपनी टीम में शामिल करने में सफल रही। किंग्स इलेवन पंजाब इस नीलामी में सबसे ज्यादा 42.70 करोड़ रुपये लेकर शामिल हुआ। मैक्सवेल और कमिंस दोनों ने आईपीएल के पिछले सत्र से नाम वापस ले लिया था।

इस नीलामी में बड़ी रकम पाने वालों में दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मौरिस भी शामिल रहे, जिनके लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु ने 10 करोड़ रुपये की बोली लगाई। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल की मूल कीमत 50 लाख रुपये थी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब ने उनके लिए दिल खोलकर खर्च किया और साढ़े आठ करोड़ रुपये में टीम के साथ जोड़ा।

ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच को रॉयल चैलेंजर्स ने 4.4 करोड़ रुपये में खरीदा। क्रिस लिन को मुंबई इंडियंस ने मूल कीमत दो करोड़ रुपये में खरीदा। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5.25 करोड़ रुपये की सर्वाधिक बोली लगाई। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके पीयूष चावला को चेन्नई सुपरकिंग्स ने 6.75 करोड़ रुपये में खरीदा।

इस नीलामी में भारतीय टेस्ट खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी को निराशा हाथ लगी, जिनके लिए किसी भी फ्रैंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टीन को कोई खरीदार नहीं मिला। (शेष पृष्ठ 12 पर)

ग्राफिक्सः दीपक शर्मा

खबरों में रहे स्टॉक

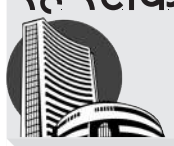

येस बैंक

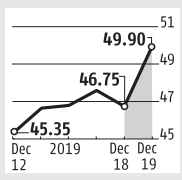

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 46.75 पिछला बंद भाव
₹ 49.90 आज का बंद भाव
▲ 6.74 %

क्लेरिएंट केमिकल्स इंडिया

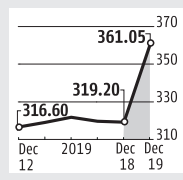

मास्टरबैच कारोबार पॉलीवन पॉलीमर को बेचा

₹ 319.20 पिछला बंद भाव
₹ 361.05 आज का बंद भाव
▲ 13.11 %

एनएमडीसी

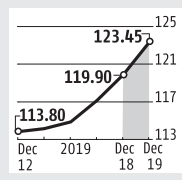

कर्नाटक के कुमारस्वामी खदान में उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर

₹ 119.90 पिछला बंद भाव
₹ 123.45 आज का बंद भाव
▲ 2.96 %

टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज

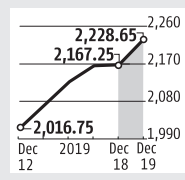

वीआईएवीआई सॉल्यूशंस संग साझेदारी में विस्तार

₹ 2,167.25 पिछला बंद भाव
₹ 2,228.65 आज का बंद भाव
▲ 2.83 %

लेमन ट्री

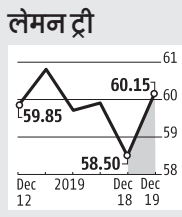

गोवा में होटल खोलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

₹ 58.50 पिछला बंद भाव
₹ 60.15 आज का बंद भाव
▲ 2.82 %

संक्षेप में

ईवी से घटेगी पेट्रोलियम पर निर्भरता: गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अवागमन का भविष्य है और जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता कम करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनी एमजी मोटर इंडिया की देश में असेंबल पहले इलेक्ट्रिक वाहन एमजी जेडएस ईवी को पेश किया। एमजी मोटर इंडिया ने बताया कि वह देश में पांच चरणों वाली चार्जिंग बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। *भाषा*

मारुति ने ऑल्टो का नया उन्नत मॉडल उतारा

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजूकी ने अपनी छोटी कार ऑल्टो का नया उन्नत संस्करण बाजार में उतारा है। इसकी शोरूम कीमत 3.80 लाख रुपये रखी गई है। मारुति सुजूकी के इस संस्करण को एरो एज डिजाइन, बेहतर आंतरिक साज सज्जा, उच्च ईंधन दक्षता और नए सुरक्षा उपायों के साथ लाया गया है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा है, मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड गुरुवार को अपनी नई ऑल्टो वीएक्सआई-प्लस को पेश करने की घोषणा करती है। नए संस्करण में स्मार्टप्ले स्टूडियो भी है जिसमें 17.8 सेंटीमीटर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स लगा है। इसे ऐंड्रायड ऑटो और ऐप्पल कार प्ले के साथ लाया गया है। *भाषा*

रेनो जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाएगी

फ्रांस की वाहन कंपनी रेनो ने जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन लागत और जिंस की लागत बढ़ने की वजह से उसे कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। कंपनी ने कहा है कि वह जनवरी 2020 से अपने वाहनों की श्रृंखला की कीमतों में इजाफा करेगी। रेनो इंडिया फिलहाल प्रवेश सतर की छोटी कार क्विड से लेकर एसयूवी कैप्चर की बिक्री करती है। इनकी कीमत दिल्ली शोरूम में 2.3 से 12.99 लाख रुपये के बीच है। *भाषा*

ई-वाहनों को टाटा समूह का दम

टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को समूह की कंपनियों की ताकत से देगी रफ्तार

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए समूह की कंपनियों की ताकत का इस्तेमाल करेगी। हालांकि कंपनी ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टाटा पावर के साथ करार किया है लेकिन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वह अपने समूह की खुदरा श्रृंखला क्रोमा की मदद लेगी ताकि वाहनों का डिजिटल प्रदर्शन किया जा सके।

टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार एवं कॉरपोरेट रणनीति) शैलेष चंद्र ने कहा, 'हमें गर्व है कि हमारे समूह की कंपनियां विविध कारोबार करती हैं और उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विशेषज्ञता प्राप्त है। हम इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी ताकत का फायदा उठाएंगे।' उन्होंने कहा, 'हम इस वित्त वर्ष के अंत तक 300 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जिसमें से 50 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।'

वाहनों के कलपुर्जे बनाने वाली समूह की कंपनी टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स ने इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी पैक बनाने के लिए चीन की कंपनी गोजुआन के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। इस संयुक्त उद्यम ने पुणे में एक प्रोटोटाइप विनिर्माण संयंत्र भी स्थापित किया है। साथ ही उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डीसी फास्ट चार्जर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ट्राइटियम के साथ साझेदारी भी की है।

चंद्रा ने कहा कि क्रोमा स्टोरों में इलेक्ट्रिक कार की डिजिटल झलक दिखाने का उद्देश्य आउटलेट में आने वाले ग्राहकों को रिझाना है। उन्होंने कहा, 'हम तकनीकी पसंद ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई ऐपल का उत्पाद खरीदने जा रहे हैं तो वह इलेक्ट्रिक पर विचार कर सकते हैं।'

चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस सप्ताह के आरंभ में आयोजित टाटा मोटर्स की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा था कि मांग को रफ्तार देने के लिए सरकार द्वारा की गई हालिया घोषणाओं के बाद कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी योजना पर नए सिरे से गौर किया है। उस योजना के तहत कंपनी निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के कई मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है।

कंपनी ने आज नेक्सन ईवी का अनावरण किया। यह व्यक्तिगत खरीदारों के लिए कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल है जिसमें कंपनी की नई इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक प्लेटफॉर्म जिपट्रॉन का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रा ने दावा किया कि यह एसयूवी मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन और पारंपरिक आईसी इंजन वाहनों के बीच मूल्य में अंतर को पाटेगा। कीमत में अंतर ही इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले कहा था कि 10 लाख रुपये से कम कीमत श्रेणी में जब तक कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं आएगा, तब तक भारत के व्यक्गित कार श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाना असंभव है।

इलेक्ट्रिक वाहन की दमदार तैयारी

- कंपनी का चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा पावर के साथ करार
- बिक्री को बढ़ावा देने के लिए समूह की खुदरा श्रृंखला क्रोमा की मदद लेगी उसके स्टोरों में वाहनों का डिजिटल प्रदर्शन करेगी
- कंपनी ने नेक्सन इलेक्ट्रिक वाहन का अनावरण किया

यामाहा का 125 सीसी स्कूटर श्रेणी में आगाज

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 19 दिसंबर

- कंपनी 2025 तक दोपहिया श्रेणी में हासिल करेगी 10 फीसदी बाजार हिस्सेदारी
- कंपनी ने फसीनो 125 एफआई, रे जेडआर 125 एफआई व स्ट्रीट रैली 125 एफआई संग दस्तक दी
- फसीनो 125 एफआई की कीमत दिल्ली में 66,430 रुपये से 69,930 रुपये के बीच रखी गई

दोपहिया वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी यामाहा ने भारत के दोपहिया बाजार में 2025 तक 10 फीसदी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी को करीब 23 लाख वाहनों की बिक्री करने की जरूरत होगी। कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि मौजूदा आर्थिक मंदी तात्कालिक है और जल्द ही मांग में सुधार होगा।

कंपनी ने आज 125 सीसी स्कूटर श्रेणी में उतरने की घोषणा की। इस श्रेणी के उत्पाद बीएस6 उत्सर्जन मानदंड के अनुरूप होंगे और कंपनी अब 110 सीसी स्कूटर श्रेणी को बंद करेगी। कंपनी ने अपने फसीनो 125 एफआई (फ्यूल इंजेक्टेड), रे जेडआर 125 एफआई और स्ट्रीट रैली 125 एफआई मॉडलों के साथ 125 सीसी स्कूटर श्रेणी में दस्तक दी है।

फसीनो 125 एफआई की कीमत दिल्ली में 66,430 रुपये से 69,930 रुपये के बीच रखी गई है।

यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मोतोफुमी शितारा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'भारत को लेकर हम काफी उत्साहित हैं।' कमजोर उपभोक्ता धारणा के अलावा विनियमन, ऋण, अधिक बीमा लागत आदि तमाम कारणों से उद्योग प्रभावित हुआ है।

भारत में शौकीन युवाओं की बड़ी आबादी है और कंपनी को विश्वास है कि मांग में जल्द सुधार होगा। युवा पीढ़ी विशेष प्रीमियम उत्पादों को पसंद करती है। कंपनी के लक्ष्य के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, '2025 तक इस उद्योग की बिक्री 2.3 करोड़ दोपहिया वाहनों की होगी और हम उसमें 10 फीसदी बाजार हिस्सेदारी यानी 23 लाख वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रख रहे हैं।'

हालांकि मोटरसाइकल श्रेणी में नजर प्रीमियम और डिलक्स उत्पादों पर होगी जबकि बिक्री को स्कूटरों से रफ्तार मिलेगी। प्रीमियम मोटरसाइकल श्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी इस साल बढ़कर 9.6 फीसदी हो गई जो पिछले साल पहले 8.5 फीसदी थी। आज स्कूटर श्रेणी का योगदान करीब 40-45 फीसदी है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अनुपात में आगे बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि आज उद्योग की करीब आधी बिक्री स्कूटर श्रेणी से आती है।

यामाहा वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन उतार चुकी है और इस साल उसने ताइवान में इलेक्ट्रिक वाहन उतारा है। लेकिन भारत में बुनियादी ढांचा और लागत इस श्रेणी के लिए महत्त्वपूर्ण कारक हैं। शितारा ने कहा कि ग्राहकों के लिए ई-वाहन की शुरुआती लागत भी अधिक है। कंपनी ने पिछले चार वर्षों के दौरान भारत में करीब 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है और बीएस6 के लिए 14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया गया है।

यामाहा मोटर इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (रणनीति एवं नियोजन) रवींद्र सिंह ने कहा कि साल 2019 इस उद्योग के लिए एक कठिन वर्ष रहा। बाजार में कंपनी के नए स्कूटरों की टक्कर हीरो, होंडा, टीवीएस, सुजूकी एवं अन्य कंपनियों के उत्पादों से होगी। साल 2019 में 125 सीसी श्रेणी का बाजार करीब 13 लाख वाहनों का रहा और 2018 के मुकाबले इसमें करीब 7.6 फीसदी की वृद्धि हुई।

हुंडई को दूसरी छमाही तक बाजार में सुधार की आस

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 19 दिसंबर

कार बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया ने उम्मीद जताई है कि अगले साल दूसरी छमाही तक बाजार में सुधार होगा। कंपनी ने कहा है कि वह अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगी क्योंकि उसके पास उत्पादों की व्यापक श्रृंखला है जिस पर वह मंदी के बावजूद निवेश कर रही है।

कंपनी ने आज अपनी नई सिडैन ऑरा का अनावरण किया जो बाजार में मारुति की डिजायर और होंडा की अमेज को टक्कर देगी। कंपनी ने इस मॉडल पर करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और यह कंपनी की रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत उसने 2022 तक 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की बात कही है। कंपनी ऑटो एक्सपो में वैश्विक स्तर पर इस मॉडल को उतारेगी। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ एसएस किम ने आज ऑरा का अनावरण करने के बाद कहा कि साल 2019 के दौरान इस उद्योग में 13 फीसदी की गिरावट आई जबकि हुंडई को करीब 7 फीसदी का झटका लगा लेकिन उसके निर्यात में 20 फीसदी की वृद्धि हुई। उपभोक्ता धारणा के अलावा अन्य तमाम कारणों से उद्योग प्रभावित हुआ जिसमें विनियमन, लागत में वृद्धि आदि शामिल हैं। कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को बढ़ी हुई लागत ग्राहकों के कंधों पर खिसकाना जरूरी है। इसके अलावा अप्रैल से नए उत्सर्जन मानदंड बीएस6 लागू होने से पहले ग्राहक अपनी खरीद योजना को फिलहाल टाल रहे हैं। यह एक प्रमुख बाधा है और दूसरी छमाही में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी जिससे वृद्धि को रफ्तार मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अलगे साल वृद्धि एकल अंक में होगी क्योंकि पहली छमाही में लगातार दबाव बरकरार रहा।

किम ने कहा कि कंपनी अपने उत्पादों के कारण उद्योग में बेहतर प्रदर्शन करेगी। क्षमता उपयोगिता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी की क्षमता करीब 7.65 लाख वाहन बनाने की है और वह करीब 7 लाख वाहनों का उत्पादन कर रही है। इनमें से करीब 20 से 25 फीसदी वाहनों का निर्यात किया जाता है।

हुंडई ने दिखाई नई सिडैन ऑरा

आईडीबीआई बैंक जुटाएगा रकम

निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीबीआई बैंक अपना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने के लिए टियर-2 बॉन्ड के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। सितंबर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सरकार ने इक्विटी पूंजी के तौर पर इस बैंक में 9,300 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इससे बैंक को पूंजी पर्याप्तता अनुपात बढ़ाने में मदद मिली और वह नियामकीय सीमा से ऊपर आ गया। उस पूंजी निवेश के बाद बैंक लाभप्रदता को छोड़कर सभी त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) मानदंडों पर खरा उतर गया। क्रिसिल ने एक बयान में कहा कि इससे आईडीबीआई बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी से अपने बैंकिंग परिचालन को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। *बीएस*

एफएमसीजी कंपनियों का जोर प्रीमियम, छोटे पैक पर

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 19 दिसंबर

रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियां बाजार में मंदी के बीच अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए छोटे पैक पर जोर दे रही हैं। लेकिन प्रीमियम उपभोक्ताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और उनके लिए नए लॉन्च किए जा रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के एफएमसीजी समिट के दौरान इस उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से यह बात कही।

केवल पिछली दो तिमाहियों के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), नेस्ले, प्रॉक्टर ऐंड गैम्बल और मोंडलीज जैसी कंपनियों ने डिटरजेंट, पर्सनल केयर और फूड श्रेणी में कई प्रीमियम उत्पादों को लॉन्च किया है। जबकि उनके उत्पाद पोर्टफोलियो में छोटे पैक का अनुपात बढ़ा है।

उद्योग के आकलन के अनुसार, एफएमसीजी क्षेत्र की अधिकतर कंपनियों के उत्पाद पोर्टफोलियो में छोटे पैक के अनुपात में पिछले छह महीने के दौरान 10 से 15 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसका उद्देश्य उत्पादों को ग्राहकों तक हर संभव पहुंच बढ़ाना है।

नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुरेश नारायण ने कहा, 'इस प्रकार कंपनियां सुनिश्चि कर रही हैं कि लोग कुछ सैम्पलिंग करेंगे जिससे उसकी पहुंच बढ़ेगी।'

पीऐंडजी के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में वृद्धि को रफ्तार देने के लिए उनकी कंपनी बेहतर उत्पाद, ब्रांड संचार, खुदरा निष्पादन और मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उदाहरण के लिए, पर्सनल केयर एवं लॉन्ड्री श्रेणी में प्रीमियम उत्पादों को छोटे पैक में उतारा गया है। पीऐंडजी शैम्पू के अधिक पाउच उतारने, टाइड के दाम घटाने और फेमिनिन केयर उत्पादों के कम कीमत वाले पैक उतारने पर जोर दे रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों के उत्पाद पोर्टफोलियो में छोटे पैक की वृद्धि को आगे और रफ्तार मिल सकती है क्योंकि मंदी का असर अगली कुछ तिमाहियों तक दिख सकता है। बाजार अनुसंधान एजेंसी नीलसन पहले ही अनुमान जाहिर कर चुकी है कि अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में एफएमसीजी बाजार की वृद्धि निचले एकल अंक में रहेगी। एजेंसी का कहना है कि आगामी महीनों में स्थिति कहीं अधिक खराब होने की आशंका है।

पिछली छह तिमाहियों के दौरान एफएमसीजी बाजार की वृद्धि लगातार घटी है जो जुलाई से सितंबर 2018 की अवधि में 16 फीसदी रही थी। अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि में एफएमसीजी बाजार की वृद्धि 3 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मंदी के संकेत विशेष तौर पर आधुनिक व्यापार में दिखने लगे हैं। उनका कहना है कि उत्पादों को प्रीमियम बनाना और उसकी पहुंच बेहतर करना एफएमसीजी क्षेत्र की कंपनियों की वृद्धि के लिए अभी भी सबसे अधिक कारगर उपाय है।

- बाजार में मंदी के बीच बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी की रणनीति
- डिजिटल, टीवी विज्ञापन के जरिये अपनी मौजूदगी सुनिश्चित कर रही कंपनियां

डिलिवरी कारोबार 10 वर्ष के निचले स्तर के नजदीक

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 19 दिसंबर

शेयर बाजार के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी डिलिवरी-आधारित कारोबार का सिलसिला इस साल भी बरकरार रहा। विश्लेषकों के अनुसार, निवेशकों ने अपने कारोबार पर बड़े नुकसान से बचने या कम मुनाफा कमाने के लिए बड़ी तादाद में सौदों को अगले दिन (डिलिवरी में) ले जाने के बजाय इंट्राडे में ही उनका निपटान करना ज्यादा उचित समझा।

बाजार कारोबारियों का कहना है कि डिलिवरी-आधारित कारोबार में कमी बाजार के मंदी से गुजरने का संकेत है।

डिलिवरी आधारित कारोबार में अप्रैल 2019 में गिरावट आई है। नवंबर के लिए यह 33.2 प्रतिशत पर दर्ज किया गया, वहीं महीने के लिए औसत दैनिक बाजार कारोबार में तेजी आई। दिसंबर के पहले दो सप्ताहों के लिए डिलिवरी प्रतिशत 30.6 पर था, जबकि इस अवधि के लिए दैनिक हाजिर बाजार कारोबार 35,913 करोड़ रुपये रहा। यदि दिसंबर के लिए डिलिवरी प्रतिशत मौजूदा स्तरों पर बना रहता है तो यह पिछले 10 वर्षों में सबसे कम होगा।

पिछले 14 वर्षों में, मासिक हाजिर बाजार कारोबार सिर्फ 6 अवसरों पर 40,000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा। कम डिलिवरी मात्रा के साथ ऊंचा कारोबार बाजार गतिविधि में तेजी और इसकी दिशा में विश्वास के अभाव का संकेत है।

बाजार कारोबारियों का मानना है कि कारोबारी अपने पोजीशन जल्द निपटाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में कोई स्पष्ट रुझान नहीं दिख रहा है और इससे डिलिवरी कारोबार में गिरावट को बढ़ावा मिल रहा है।

मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'जैसे ही बाजार में किसी दिशात्मक रुझान विकसित होता है, जैसा कि मौजूदा बाजार में मामले में है, अटकलों से जुड़ी गतिविधि तेज हो जाती है। दूसरी बात, म्युचुअल फंडों का प्रवाह कमजोर पड़ रहा है और इससे बाजार में इक्विटी डिलिवरी पर प्रभाव दिख रहा है। म्युचुअल फंड हाजिर बाजार में बेहद सक्रिय कारोबारी रहे हैं। जब म्युचुअल फंड प्रवाह में सुधार आएगा, आप वायदा एवं विकल्प में गतिविधि के विपरीत ज्यादा डिलिवरी कारोबार देखेंगे।'

घरेलू चिंताओं और कुछ वैश्विक समस्याओं की वजह से बाजार पूरे वर्ष अस्थिर बना रहा। वैश्विक रूप से, अनिश्चित ब्रेक्सिट, अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव, और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका ने निवेशकों को साल के ज्यादातर समय के दौरान चिंतित बनाए रखा।

घरेलू मोर्चे पर, कॉरपोरेट डिफॉल्ट के बढ़ते मामलों, कमजोर आय वृद्धि, और धीमी आर्थिक वृद्धि मुख्य चिंताएं रहीं। सितंबर तिमाही के लिए जीडीपी 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो 6 वर्षों में इसकी सबसे कमजोर वृद्धि थी। इसके अलावा वित्तीय कंपनियों की सेहत को लेकर भी आशंकाओं से निवेशकों में अनिश्चितता पैदा हुई।

- भले ही बाजारों ने नए ऊंचे स्तर छुए हैं, लेकिन निवेशक दीर्घावधि पोजीशन लेने से परहेज कर रहे हैं
- डिलिवरी आधारित कारोबार में अप्रैल 2019 में गिरावट आई है। नवंबर के लिए यह 33.2 प्रतिशत पर दर्ज किया गया
- कारोबारियों का मानना है कि कारोबारी अपने पोजीशन जल्द निपटाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में कोई स्पष्ट रुझान नहीं दिख रहा

अयस्क और इस्पात क्षमता बढ़ेगी

ईशिता आयान दत्त और अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 19 दिसंबर

- **जेएसडब्ल्यू स्टील अगले साल डोल्वी में अपना 50 लाख टन का विस्तार पूरा कर सकती है**
- **एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2021 में अपने 30 लाख टन क्षमता वाले नए संयंत्र को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा है**

देश के प्रमुख इस्पात एवं लौह अयस्क उत्पादकों द्वारा अगले दो वर्षों में कम से कम 1.3 करोड़ टन क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। उत्पादकों द्वारा बाजार में ऐसे समय में क्षमता में यह वृद्धि किए जाने का अनुमान है जब बाजार 3 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

निजी क्षेत्र में, जेएसडब्ल्यू स्टील अगले साल डोल्वी में अपना 50 लाख टन का विस्तार पूरा कर सकती है, कलिंगनगर में टाटा स्टील का दूसरे चरण का विस्तार चल रहा है और इसके कैलेंडर वर्ष 2021 तथा वित्त वर्ष 2022 के बीच पूरा हो जाने की संभावना है। सरकार के स्वामित्व वाली एनएमडीसी ने वित्त वर्ष 2021 में अपने 30 लाख टन क्षमता वाले नए संयंत्र को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2018-19 में क्षमता वृद्धि करने वाली सेल अब इसमें सुधार लाए जाने की प्रक्रिया से गुजर रही है।

एएम/एनएस इंडिया मध्यावधि में अपनी खेपें बढ़ाकर 85 लाख टन और दीर्घावधि में 1.2-1.5 करोड़ टन किए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इस बारे में सही समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं मौजूदा समय में एएम/एनएस की अधिकतम क्षमता 96 लाख टन की है, हालांकि यह फिलहाल 75 लाख टन का उत्पादन कर रही है।

जहां अगले दो वर्षों में 1.3 करोड़ टन क्षमता जुड़ने की संभावना है, वहीं 2024-2025 तक मंत्रालय मौजूदा कंपनियों के चालू नियोजित क्षमता विस्तार से 2.8-3 करोड़ टन क्षमता की उम्मीद कर रहा है।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयंत रॉय ने कहा, 'वित्त वर्ष 2001-वित्त वर्ष 2016 के दौरान घरेलू इस्पात उत्पादन और खपत दोनों में लगभग 7.9 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वित्त वर्ष 2017-वित्त वर्ष 2020 के दौरान इस्पात उत्पादन और खपत में 3 और 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी तिमाही के लिए सालाना आधार पर वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 3 प्रतिशत से कुछ ऊपर रही।'

हालांकि रॉय ने स्पष्ट किया कि यदि घरेलू क्षमता अगले 3-4 साल में 2 करोड़ टन तक बढ़ती है तो इसके लिए खपत में 4-5 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की जरूरत होगी जिससे कि 78-80 प्रतिशत के मौजूदा क्षमता इस्तेमाल को बरकरार रखा जा सके। जेएसडब्ल्यू के निदेशक (वाणिज्यिक एवं विपणन) जयंत आचार्य ने कहा, 'भारत वृद्धि की राह पर है। कम जीडीपी वृद्धि का एक वर्ष बुनियादी आधार नहीं बदलेगा। वृद्धि की रफ्तार फिर से मजबूत होगी।'

आचार्य के अनुसार, मांग परिदृश्य में पहले ही कुछ सुधार आया है और यात्री कार बिक्री में इसका असर दिखा है। कंज्यूमर अप्लायंस के परिदृश्य से भी मौसमी मांग में तेजी स्पष्ट दिखी है। कोरियाई फर्म पोस्को के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक जी एच बांग का भी कहना है कि मांग में कुछ सुधार आया है।

जेट एयरवेज पर निर्णय में विलंब न करे सिनर्जी समूह

अनीश फडणीस
मुंबई, 19 दिसंबर

राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट (एनसीएलटी) ने सिनर्जी ग्रुप से जेट एयरवेज के कायाकल्प को लेकर अपनी निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।

दक्षिण अमेरिकी समूह हवाई अड्डा स्लॉटों पर अनिश्चितता की वजह से 16 दिसंबर की समय-सीमा से पहले अपनी समाधान योजना सौंपने और ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तावित ताजा बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने में विफल रहा है।

सिनर्जी के कार्यकारी अध्यक्ष मिशेल वेल्स ने एनसीएलटी के मुंबई पीठ को जानकारी दी कि समूह जेट की सभी संपत्तियों, कर्मचारियों और उसके परिचालन परमिट (लेकिन देनदारियां शामिल न[illegible] का अधिग्रहण कर एक नई कंपनी के गठ[illegible] के जरिये एयरलाइन का कायाक[illegible] को उत्सुक है। वेल्स ने [illegible] ही यह चुनौतीपूर्ण [illegible] एक अवसर [illegible]

निवेशकों का सुरक्षित शेयरों पर रहेगा जोर

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 19 दिसंबर

क्रेडिट सुइस का मानना है कि बाजार में कारोबार सीमित दायरे में बना हुआ है, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए संस्थागत निवेशक 'सुरक्षित' शेयरों पर दांव लगाना पसंद कर रहे हैं।

ब्रोकरेज फर्म का कहना है, 'चूंकि निवेशक कमजोर आर्थिक गतिविधि स्तरों से चिंतित हैं और राजस्व में बड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई है तथा हाल की तिमाहियों में खासकर घरेलू संस्थागत खरीदारों के लिए खरीदारी काफी हद तक पिछले तीन वर्षों में केंद्रित रही।'

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का 76 प्रतिशत निवेश निफ्टी शेयरों में है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों के लिए यह 66 प्रतिशत है। एक साल पहले घरेलू निवेशकों के लिए यह अनुपात 56 प्रतिशत था। उनकी खरीदारी काफी हद तक लार्ज और लिक्विड शेयरों में सीमित रही है। कई बड़े शेयर अपने सर्वाधिक ऊंचे सतरों से 20-30 प्रतिशत या इससे भी ज्यादा नीचे आ गए हैं।

क्रेडिट सुइस में इक्विटी स्ट्रेटेजी (एशिया पैसीफिक एंड इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट) के सह-प्रमुख नीलकंठ मिश्रा ने कहा, 'हमारा मानना है कि प्रमुख सूचकांक पूंजी प्रवाह की मदद से ऊंचे स्तर पर बने रहेंगे और ज्यादातर बाजार पूंजीकरण उत्पादों की बढ़ती पैठ, बाजार भागीदारी वृद्धि या वैश्विक कारकों आदि से संबंधित है।'

ब्रोकरेज का कहना है कि निर्माण गतिविधि में मंदी की वजह से पिछली 6 तिमाहियों में वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ी है।

ब्रोकरेज को प्रमुख सूचकांकों में तेजी बरकरार रहने का अनुमान है। उन कंपनियों से मजबूत कोष प्रवाह और आय वृद्धि से शेयर बाजार को मदद मिलेगी जो घरेलू वृहद आर्थिक कमजोरी से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुई हैं। ब्रोकरेज को वित्त वर्श 2021 की ईपीएस वृद्धि 12-14 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जो मौजूदा 28 प्रतिशत के अनुमान से कम है।

क्रेडिट सुइस के अनुसार संस्थागत प्रवाह मजबूत बने रहने का अनुमान है। उसे एसआईपी के जरिये म्युचुअल फंडों में प्रवाह बरकरार रहने की संभावना है। एफपीआई निवेश भी भारत के लिए अच्छा संकेत है। एफपीआई निवेश का बड़ा हिस्सा दीर्घावधि निवेश से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर के अंत तक एसडब्ल्यूएफ/केंद्रीय बैंकों और पेंशन फंडों का भारतीय शेयरों में 22 प्रतिशत निवेश था।

उद्यमियों ने वित्त मंत्री से मांगी कारोबार की आजादी

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी बजट टीम ने आज उद्योग जगत के प्रतिनिधियों व उद्योग संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व मशविरा लिया। उद्योगपतियों ने केंद्र से कहा कि कारोबार की राह आसान करने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं श्रमिक संगठनों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, आयकर सीमा बढ़ाने व पेंशन तय किए जाने की मांग की।

उद्योग के प्रतिनिधियों में भारती इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर और एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योग जगत को प्रदर्शन के लिए आजादी दी जानी चाहिए।

कॉर्पोरेट दिग्गजों ने कुछ अहम मसले उठाए, जिनमें कुछ आयकर व्यवधान शामिल हैं जो विलय एवं अधिग्रहण या कारोबारी मंदी की वजह से राह में आए थे। मित्तल ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं आज यहां सिर्फ एक विषय पर चर्चा करने आया हूं। देश के भीतर कारोबार करना सुगम बनाया जाए। यह मेरी प्रमुख बात थी।'

मित्तल ने कहा, 'उद्योगों के लिए ज्यादा आजादी का विचार उनके बेहतर प्रदर्शन को लेकर आया है। मेरा माना है कि वित्त मंत्री इस पर अपने सहयोगियों व सचिवों के साथ विचार करेंगी। हम बजट में यह देखना चाहेंगे कि भारत के उद्योगपतियों को उनकी क्षमता के इस्तेमाल का उचित अवसर दिया गया है।'

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका ने कहा कि कारोबार को सुगम बनाने में राज्यों की अहम भूमिका है और अंतिम समय के मसले बने हुए हैं, जिसके समाधान की जरूरत है। बैठक के बारे में पूछे जाने पर किर्लोस्कर ने कहा, 'हमने कारोबार सुगमता पर बात की, जो तमाम उद्योगों के लिए चिंता का विषय है।' आरपी संजीव गोयनका समूह के संजीव गोयनका ने कहा कि चर्चा इस पर केंद्रित रही कि वृद्धि को गति देने के लिए कारोबार सुगमता की सुविधा दी जानी चाहिए।

गोयनका ने कहा, 'मुझे लगता है कि वित्त मंत्री और उनकी टीम सभी सुझावों को लेकर बहुत उदार हैं।' उन्होंने आगे कहा कि यह पहला मौका है, जब सरकार की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है।

नई दिल्ली में गुरुवार को बजट पूर्व बैठक में उद्योगपतियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोटो-पीटीआई

तमाम उद्योगों में मौजूदा मंदी और क्षमता के इस्तेमाल पर इसके असर के बारे में गोयनका ने कहा कि उद्योग जगत ने पाया है कि क्षमता उपयोग शीर्ष पर पहुंचने में 4 तिमाही तक लग सकती है। उन्होंने कहा, 'हम इसे समझते हैं और यह स्थिति की हकीकत है।'

उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह भी सिफारिश की है कि 20 लाख रुपये सालाना से कम कमाई वालों का आयकर घटाया जाना चाहिए, जिससे ग्राहकों के हाथ में इस्तेमाल आने वाली राशि ज्यादा हो और ब्याज दरें घटाने की प्रक्रिया को जल्द उपभोक्ता के स्तर पर लाया जाए। सरकार ने बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा, 'दो घंटे तक चली बैठक में उद्योगपतियों ने नियामकीय माहौल में सुधार के माध्यम से कारोबार सुगमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निजी निवेश बहाल करने, वृद्धि को गति देने के सिलसिले में बात हुई।'

इसके पहले मजदूर संगठनों ने सरकार से अपील की कि न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपये महीने की जानी चाहिए और सालाना 10 लाख आमदनी को कर मुक्त किया जाना चाहिए।

'जीएसटी क्रेडिट पर रोक से नकद प्रवाह पर होगा असर'

दिलाशा सेठ और इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

उद्योग जगत को डर है कि जीएसटी परिषद द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की और रकम को रोके जाने से नकद प्रवाह पर असर होगा। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था में व्याप्त सुस्ती के कारण नकदी के स्रोत बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं तब जीएसटी परिषद ने सही प्रारूप में अपलोड नहीं किए गए इनवॉइसों के लिए भुगतान किए जाने वाली राशि को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

परिषद ने आज इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपने अपने आपूर्तिकर्ताओं को 1,000 रुपये कर के रूप में भुगतान किया है और अपने सारांश इनपुट-आउटपुट-फॉर्म जीएसटीआर 3बी पर इसका दावा आईटीसी के रूप में किया है, तब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके सभी आपूर्तिकर्ता सभी इनवॉइसों को अपने आपूर्ति पक्ष वाले रिटर्न- जीएसटीआर 2ए में अपलोड करें।

अब, यदि इनवॉइसों की राशि दावा किए गए आईटीसी का 20 फीसदी है और इसे आपके आपूर्तिकर्ताओं ने अपलोड नहीं किया है तब आपका पात्र क्रेडिट केवल 800 रुपये होगा। जीएसटी परिषद के निर्णय को अधिसूचित होने के बाद आप 80 रुपये के आईटीसी (800 रुपये का 10 फीसदी) दावा कर सकते हैं। इससे पहले 800 रुपये पर 160 रुपये का दावा किया जा सकता था।

अक्टूबर से पहले जीएसटीआर 3बी में जो भी दावा किया गया अधिकारियों ने पूरी रकम जारी की थी। इस साल अक्टूबर में सरकार ने इस क्रेडिट को कम कर पात्र क्रेडिट का 20 फीसदी कर दिया था जिसे अब और अधिक घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।

क्लीयर टैक्स के मुख्य कार्याधिकारी अर्चित गुप्ता ने कहा कि इस रकम को घटाकर 10 फीसदी किया जाना कारोबार के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारोबारियों को लगातार अपने आपूर्तिकर्ताओं से इनवॉइस अपलोड करने को लेकर संपर्क में रहना पड़ेगा। डेलॉइट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा आईटीसी पर रोक से फंसी हुई कार्यशील पूंजी में इजाफा होगा।

सीजीएसटी अधिनियम के तहत नियम 36(4) के तहत इस तरह के रोक प्रभावी होते हैं जिसे पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। उन्होंने कहा, 'कारोबारी इस तरह के प्रतिबंधों के हटने का स्वागत करेंगे जो जीएसटी के प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। जीएसटी में पूरी मूल्य श्रृंखला में बाधारहित क्रेडिट प्रवाह की बात है।' केपीएमजी में पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा कि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महीने दर महीने मिलान की जल्दबाजी के कारण इस 20 फीसदी या 10 फीसदी क्रेडिट को पूरी तरह से छोड़ दिया है।

ईवाई में कर पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि कर संग्रह में आ रही गिरावट और क्रेडिट धोखाधड़ी को बंद करने की बात को देखते हुए सरकार ने अज्ञात इनवॉइसों के अनुपात को घटा दिया है जिस पर क्रेडिट लिया जा सकता था।

बगैर इस्तेमाल वाली एसईजेड की जमीन पर आभूषण पार्कों की योजना

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 19 दिसंबर

आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश भर में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की खाली पड़ी जमीनों पर आभूषण पार्क बनाने की योजना बना रही है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय इस सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के समक्ष एक प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहा है, जिससे एसईजेड की जमीन के इस्तेमाल के लिए उसकी अनुमति ली जा सके। इस योजना की पुष्टि करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'हमारा मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बात कर रहा है और एसईजेड की अनुपयोगी पड़ी जमीनों पर घरेलू रत्न एवं आभूषण विनिर्माताओं के लिए देश भर में आभूषण पार्क बनाने का प्रस्ताव है।' तमाम एसईजेड में आभूषण विनिर्माण इकाइयां हैं, लेकिन किसी भी एसईजेड में विशेष आभूषण पार्क या क्लस्टर नहीं है।

वाणिज्य मंत्रालय ने मांगी वित्त मंत्रालय से अनुमति

जेम्स ऐंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के वाइस चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा, 'आभूषण पार्क से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को सामान्य सुविधा केंद्र, इससे जुड़ी सेवाओं जैसे बैंक और कारीगरों के लिए आवास के साथ अन्य सुविधाओं का तत्काल लाभ मिलेगा।' गोयल ने रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को निर्विक स्कीम (जिसे ईसीआईएल या एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम के नाम से भी जाना जाता है) में पंजीकरण का सुझाव दिया। इसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (ईसीजीसी) ने सितंबर 2019 में पेश किया था, जिससे उधारी की प्रक्रिया सरल हो सके और निर्यातकों को कर्ज की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

इस समय रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के कारोबारी कार्यशील पूंजी की भारी कमी के संकट से जूझ रहे हैं। करीब दो साल पहले हुए पंजाब नैशनल बैंक-नीरव मोदी घोटाले के बाद से बैंकों ने इस क्षेत्र को कर्ज देना कम कर दिया है। निर्विक योजना का लक्ष्य निर्यात बढ़ाना और रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को कई लाभ देना है। साथ ही सिसे निर्यातकों के लिए कर्ज तक पहुंच बढ़ेगी और उन्हें सस्ता कर्ज मिल सकेगा। साथ ही इससे निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ईसीजीसी प्रक्रिया निर्यातकों के प्रति मित्रवत और एमएसएमई निर्यातकों को लाभ पहुंचाने वाली है।

24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा पर हो रहा विचार

अनूप रॉय
मुंबई, 19 दिसंबर

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सेवा को अब 24 घंटे चालू रखने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली को चौबीस घंटे मुहैया कराने पर विचार कर रहा है। इस मामले के जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्र ने कहा कि यह फैसला एक या दो महीने में लागू हो सकता है।

आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़ी रकम को भेजने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से कम से कम 2 लाख रुपये भेजी जाती है। इस सेवा का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर व्यापारिक और बाजार लेनदेन के लिए होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों सहित 229 बैंक नवंबर तक यह सेवा मुहैया करा रहे थे। आरटीजीएस के जरिये होने वाला लेनदेन नवंबर में 86.8 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

पूरे समय के लिए इस सेवा की शुरुआत हो जाने से बड़ी संख्या में मौके सृजित होंगे।

एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने पहचान जाहिर नहीं करने के अनुरोध के साथ कहा, 'इस सेवा के शुरू होते ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में पूरे समय अंतरण और निपटान का काम हो सकेगा। इस तरह एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी।'

भले ही घरेलू बाजार तब भी सामान्य बाजार के घंटों में कार्य करते रहेंगे लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र चौबीस घंटे परिचालित होते हैं। निस्संदेह इस फैसले के प्राथमिक लाभार्थी पूंजी बाजार होंगे।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर सौम्यजित नियोगी ने कहा, 'व्यापार और पूंजी बाजार गतिविधियों के लिए यह एक अच्छा कदम होगा और यह भविष्य में पूर्ण रुपया परिवर्तनीयता के पूर्व की तैयारी साबित हो सकता है।'

वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ अश्विन पारेख के मुताबिक 24 घंटे लेनदेन की प्रणाली से व्यापार और वाणिज्य को बड़ी मजबूती मिलती है।

रिजर्व बैंक एनईएफटी लेनदेन और आरटीजीएस का इस्तेमाल कर बाहरी लेनदेनों के लिए लगने वाला शुल्क पहले ही खत्म कर चुका है। सोमवार को रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को अपने बचत खाता वाले ग्राहकों से एनईएफटी पर शुल्क नहीं वसूलना चाहिए।

रिजर्व बैंक के मुताबिक सोमवार को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक 11.40 लाख से अधिक लेनदेनों को निपटाया गया। इन लेनदेनों को शुल्क मुक्त करने से ऐसे डिजिटल खुदरा भगुतानों को और अधिक मजबूती मिल सकती है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, 'रिजर्व बैंक अब अपने देश में चौबीस घंटे किसी भी मूल्य के फंड अंतरण और निपटान की सुविधा देने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया।'

अब तक ऑस्ट्रेलिया, हॉन्गकॉन्ग, मैक्सिको, स्वीडन, तुर्की, यूके, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और चीन ऐसे देश हैं जहां चौबीस घंटे भुगतान प्रणाली से किसी भी मूल्य का फंड अंतरण और निपटान किया जाता है।

मिलेगी सेवा

- अगले एक या दो महीने में 24 घंटे मिल सकती है आरटीजीएस सेवा
- आरटीजीएस का इस्तेमाल बड़ी रकम भेजने के लिए किया जाता है
- इसका इस्तेमाल व्यापारिक लेनदेन के लिए ज्यादा

सिर्फ 9 राज्यों का मुआवजा 70,000 करोड़ रुपये : इक्रा

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 19 दिसंबर

रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि आर्थिक मंदी की वजह से 2019-20 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में कमी के कारण सिर्फ 9 राज्यों को ही 70,000 करोड़ रुपये मुआवजा देने की जरूरत होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल उन 9 राज्यों में शामिल हैं। सभी राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए कहीं और ज्यादा धन की जरूरत होगी।

अब तक 3 किस्तों में सभी राज्यों को अप्रैल से सितंबर तक (वित्त वर्ष की पहली छमाही का) के करीब 80,000 करोड़ रुपये मुआवजे का भुगतान केंद्र ने किया है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक खबर में बताया था कि पूरे वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को मुआवजा उपकर से 63,000 करोड़ रुपये कम मिलेंगे। बहरहाल केंद्र सरकार के लिए राहत यह है कि उसे राज्यों को 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये इस साल बंटवारे में कम देने होंगे क्योंकि उसने 2018-19 में अतिरिक्त राशि दी थी।

बीएस सूडोकू 3617 | परिणाम संख्या 3616

					3			
5	7	3						2
	8	9	7		2			
		1			7	5		3
			5		8			
4		5	3			9		
			4		6	1	3	
6						4	9	8
			8					

2	4	6	8	5	7	9	1	3
7	1	5	2	3	9	6	4	8
9	8	3	4	1	6	7	2	5
6	5	8	9	4	1	3	7	2
4	9	2	5	7	3	8	6	1
1	3	7	6	8	2	4	5	9
3	7	4	1	2	8	5	9	6
5	6	1	3	9	4	2	8	7
8	2	9	7	6	5	1	3	4

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2100/2120, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1445, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1525, फ्लैक 1465, डीएमओ 1055, टरपीन लैस बोल्ड 1555

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1250/1270, खुरपा 1150/1170, चाकू 1175/1250, रसकट 870/875, शक्कर 1230/1260, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3300, सिहोरा 3155, बुढ़ाना 3260, शामली 3215,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1050, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4400, खल: सरसों 2250/2350,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5550/5650, गेहूं (मिल) 2165/2175, मक्की 2200/2225, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2800/2900,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3825, जौ 2000/2010, सरसों लूज 4150/4200

जोधपुर
गेहूं 2050/2080, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1930/1935, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4200/4250, काबली चना 4800/6000, मूंग 6100/6300,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बेच सफेद 1250, लाल 1230, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7000/8000, अरहर दाल 7700/8300, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9600/10600, छिलका 9100/10100, दाल मसूर 5700/6000, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250, चावल 1509 सेला 5150/5250, धान: शरबती 2100/2150, बासमती 1121 धान 2850/2900,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3950/3980, हरियाणा 3930/3980, राजस्थान 3880/3925, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2500, सरसों खल 2220/2225,

फाजिल्का
गेहूं 2150/2160, सरसों 4450/4475 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/4000, कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5150/5350, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2140/2150, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2300/2310, बिहार 2365/2370, दाल उड़द छिलका 8800/10600, चना देशी 5000/5100, दाल चना 5200/5450, काबली चना 4900/5750, राजमां चित्रा पुणे 7000/8300, चीन 7200/7800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2160/2170, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2550/2600, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 5950/6150,

हिसार
ग्वार 3800/3825, जौ 1775/1780, सरसों 4200/4250, मूंग 6700/6800, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2300/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9200/9250, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1800/1850 एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 261

जीएसटी पर प्रतिक्रिया

अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की निगरानी करने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 38वीं बैठक बुधवार को हुई। परंतु यह बैठक अन्य बैठकों से अलग थी।

इस परिषद में राज्यों और केंद्र के वित्त मंत्री शामिल हैं और अब तक परिषद की बैठक में सर्वस्वीकृति की परंपरा थी जहां किसी भी बदलाव पर सभी सहमत होते थे। पहली बार, यहां मतदान के जरिये लॉटरी पर लगने वाली कर दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध जारी रखा।

संभव है कि कोई अन्य विकल्प नहीं रहा हो लेकिन यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। निश्चित तौर पर जीएसटी में दिक्कतें नजर आ रही हैं। राज्य भी जीएसटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति को लेकर काफी चिंतित हैं क्योंकि वह समय पर नहीं मिल रही है।

इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव उत्पन्न हुआ है। इसके बावजूद जीएसटी का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। यह बात इस वक्त इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कॉर्पोरेट आय कर में कमी आई है और कॉर्पोरेशन कर अक्टूबर से दिसंबर 2019 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5 फीसदी तक कम हुआ है। व्यक्तिगत आय कर में पर्याप्त वृद्धि नजर नहीं आ रही है ताकि इसकी भरपाई हो सके।

इससे यह संकेत निकलता है कि इसके लिए मंदी भी आंशिक तौर पर उत्तरदायी है। ऐसे में कम जीएसटी संग्रह राजकोषीय संकट पैदा कर रहा है।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये मासिक का लक्ष्य तय किया था। चालू वर्ष के पहले महीने को छोड़ दिया जाए तो अब तक इतनी राशि एकत्रित नहीं हो सकी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यापक कर वंचना और इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में धोखाधड़ी की धारणा जोर पकड़ रही है।

इस मसले को हल करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्षेत्र में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कई तरीके भी प्रस्तावित हैं। मिसाल के तौर एक सुझाव यह है कि इनवॉइस अपलोड होने के पहले मुहैया कराई जाने वाली राशि को मौजूदा 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की बात। परंतु सरकार को कर वंचना से निपटने को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आमतौर पर कर अधिकारियों को लक्ष्य देना और उन लक्ष्यों को हासिल करने के अधिकार देना देश में अनुत्पादक साबित हुआ है।

फिलहाल विचार है कि देर से फाइलिंग करने वालों को जुर्माने से राहत देकर देखा जाए। इसके अलावा समयसीमा में इजाफा भी किया जा सकता है। परंतु ऐसा लगता है कि कड़े उपायों पर भी सहमति बन रही है। इसमें जुर्माना बढ़ाना और कर अधिकारियों को अधिक अधिकार सौंपना शामिल है।

स्वाभाविक है कि नीतिगत बदलाव में लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी शामिल की जा रही है। बहरहाल, सरकार को समग्रता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए।

जीएसटी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि कर मामलों में लोग स्वैच्छिक हिस्सेदारी करें। ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने से मासूम और दोषी दोनों चपेट में आएंगे और ऐसे वक्त में देश का कारोबारी रुझान कमजोर होगा जब कारोबारी भावनाओं को जीवंत बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

जरूरत यह है कि जीएसटी ढांचे पर समग्र दृष्टि डाली जाए। देखा जाए कि क्या इसे आसान बनाकर अनुपालन बढ़ाया जा सकता है? परिषद को कर और विशिष्ट दरों को लेकर भी व्यापक दिशा स्पष्ट करनी चाहिए।

अजय मोहंती

वृद्धि दर बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन जरूरी

सुस्ती के दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र वृद्धि की राह पर लाने के लिए निर्यात स्थिरता का दौर खत्म करना होगा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं **शंकर आचार्य**

भारतीय अर्थव्यवस्था एक गहरी एवं व्यापक होती सुस्ती के बीच में है। आर्थिक वृद्धि दर लगातार छह तिमाहियों से गिरते हुए सितंबर तिमाही में 4.5 फीसदी पर आ चुकी है और हालात जल्द सुधरने की गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। इस बात पर मीडिया एवं अन्य क्षेत्रों में काफी चर्चा हो रही है कि कुल मांग के उपभोग और निवेश जैसे मुख्य अवयवों में कैसे तेजी लाई जाए और क्या मुश्किल राजकोषीय स्थिति में सरकारी व्यय बढ़ाने की गुंजाइश बाकी है? आश्चर्यजनक ढंग से निर्यात के बारे में चर्चा लगभग नदारद है।

फिर भी वर्ष 2013-14 तक उत्पादों एवं सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 फीसदी था जो सरकारी व्यय की हिस्सेदारी से अधिक और निर्धारित निवेश से थोड़ा ही कम है। दुर्भाग्य से, भारत का उत्पाद निर्यात वर्ष 2011-12 से ही करीब 300 अरब डॉलर पर स्थिर रहने से कुल निर्यात का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 20 फीसदी से नीचे आ गया और उत्पाद निर्यात की हिस्सेदारी 12.4 फीसदी पर आ गई। वैश्विक विकास अनुभव बताते हैं कि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था निर्यात में सशक्त वृद्धि बनाए रखे बगैर तीव्र आर्थिक वृद्धि (सात फीसदी से अधिक) नहीं कायम रख पाई है। खुद हमारा अनुभव भी ऐसा ही है। भारत की आर्थिक वृद्धि के दो बेहतरीन दौर (1992-97 और 2003-11) में निर्यात वृद्धि का सिलसिला मजबूत रहा था। निर्यात गतिविधियों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं और भारत में एमएसएमई क्षेत्र का उत्पाद निर्यात में हिस्सा परंपरागत तौर पर 35-40 फीसदी रहा है। कुछ हद तक कमजोर बाह्य वित्त को मजबूती देने के लिए भी निर्यात वृद्धि जरूरी है। फिर निर्यात को नजरअंदाज करने वाली नीति को पलट क्यों देते हैं?

नीतियों में बदलाव करने के पहले हमें उस भ्रामक धारणा से भी निपटना है जिसके मुताबिक भारत की व्यापार नीतियों में खास गड़बड़ी नहीं है और हमारी निर्यात स्थिरता वर्ष 2011 के बाद वैश्विक कारोबार में आई स्थिरता के चलते है। वास्तव में, उसके बाद से वैश्विक निर्यात वृद्धि डांवाडोल रही है। लेकिन हमने तीव्र वृद्धि के दोनों ही चरणों में वैश्विक निर्यात वृद्धि को मात दी है। इसके अलावा हमसे उलट कुछ अन्य एशियाई देशों ने हाल के वर्षों में काफी अच्छा काम किया है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2018 के बीच भारत का उत्पाद निर्यात केवल आठ फीसदी ही बढ़ा है जबकि इसी अवधि में वियतनाम ने 154 फीसदी, कंबोडिया ने 114 फीसदी, म्यांमार ने 82 फीसदी, बांग्लादेश ने 61 फीसदी, फिलीपींस ने 40 फीसदी और चीन ने 31 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की। तीव्र निर्यात वृद्धि का मतलब बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से है। वर्ष 2011 और 2018 के बीच विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा 1.7 फीसदी पर स्थिर बना रहा जबकि वियतनाम का हिस्सा लगभग दोगुना, म्यांमार का 80 फीसदी, बांग्लादेश का 50 फीसदी से अधिक, फिलीपींस का 27 फीसदी और व्यापार युद्ध में उलझने के बावजूद चीन का हिस्सा 20 फीसदी से अधिक बढ़ा। विश्व निर्यात में चीन की हिस्सेदारी पिछले सात वर्षों में 2.4 फीसदी बढ़ गई जो वर्ष 2018 में भारत की कुल हिस्सेदारी से 60 फीसदी अधिक है।

लिहाजा हमें विश्व व्यापार प्रवृत्तियों को दोष नहीं देना चाहिए। सही नीतियों के साथ हम विश्व निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं जिससे जीडीपी, रोजगार, एमएसएमई आउटपुट और सशक्त बाह्य वित्त में बढ़ोतरी का लाभ मिल सके। इसके उलट मौजूदा अपर्याप्त नीतियों के चलते निर्यात में स्थिरता बनी रह सकती है जिसके नकारात्मक असर समग्र आर्थिक वृद्धि, रोजगार और बाह्य वित्तीय व्यवहार्यता पर हो सकते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि निर्यात के मोर्चे पर हमारे कमजोर प्रदर्शन को सुधारने के लिए कौन से नीतिगत कदम उठाने होंगे? हमें कम मजदूरी पर काम कर रहे श्रमिकों को बेहतर शिक्षा देने और कुशल बनाने, संपर्क एवं भंडारण सुविधा बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में एवं बेहतर ढांचे के निर्माण के अलावा सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता सुधारने, भूमि एवं श्रम कानूनों में सुधार और अपने खस्ताहाल वित्तीय प्रणाली में नई जान फूंकनी होगी। इन कदमों से कुल आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी जिससे एक प्रतिस्पर्द्धी एवं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

संक्षिप्त एवं मध्यम अवधि के भुगतान से विदेश व्यापार नीतियों का दायरा कम होने से हमारा ध्यान उन नीतियों पर होना चाहिए जिन्होंने पिछले सात वर्षों से निर्यात को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनमें चार नीतियां खास तौर पर अहम हैं। पहली, हमारी मुद्रा के मौजूदा अधिमूल्यन को दुरुस्त करना है क्योंकि यह निर्यात पर कर लगाने एवं आयात को सब्सिडी देने के बराबर है। आंकड़े बताते हैं कि इस दशक में रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर खासी अधिक रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के 36 देशों के सूचकांक से यह पता चलता है।

इस अधिमूल्यन में गिरावट आने से न केवल निर्यात को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे तीन वर्षों से जारी आयात शुल्क संरक्षण को भी पलटने में मदद मिल सकती है। हमें इस बात को मानना होगा कि ऊंचे आयात शुल्क न केवल अक्षम एवं उच्च लागत वाले घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हैं बल्कि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के महंगा होने से निर्यात भी हतोत्साहित होता है। कोई भी देश आयात शुल्क संरक्षण की राह पर चलते हुए उच्च निर्यात वृद्धि कायम नहीं रख सकता है। अगर हम तीव्र निर्यात वृद्धि बहाल करने को लेकर गंभीर हैं तो हमें हाल के वर्षों में की गई आयात शुल्क वृद्धि को वापस लेना होगा। और मुद्रा अधिमूल्यन की पृष्ठभूमि में ऐसा करना कहीं अधिक आसान होगा।

तीसरी, हमें यह समझना चाहिए कि गत दो दशकों में विश्व व्यापार वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक (एवं क्षेत्रीय) मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) से चालित होता रहा है। यह महज संयोग नहीं है कि तीव्र निर्यात वृद्धि के अधिकांश प्रतिमान भारत की तुलना में जीवीसी में कहीं बेहतर ढंग से अंतर्निहित हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भले ही जीवीसी की अहमियत स्वीकार की, लेकिन व्यापक एवं अप्रत्याशित आयात शुल्क की तरफ लौटना जीवीसी में सफल भागीदारी को कमतर बनाता है। जीवीसी में भागीदारी के लिए नगण्य या निम्न आयात शुल्क होना और उत्पादों की सरल एवं सीमापार आवाजाही जरूरी है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) समझौते का संस्थापक सदस्य बनने से हमारे इनकार का हमारे व्यापार एवं निर्यात संभावनाओं पर असर समय बीतने के साथ गंभीरता से महसूस किया जाएगा। अगर अब भी इस समझौते का हिस्सा बन पाना संभव है तो हमें आरसेप का हिस्सा बन जाना चाहिए। अन्यथा, समय बताएगा कि हमने व्यापार नीति में एक ऐतिहासिक भूल कर दी थी।

चौथी, जीएसटी लागू होने के बाद से ही निर्यातक इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधूरे एवं विलंबित भुगतान की शिकायतें लगातार करते रहे हैं। हमें प्रक्रियागत सुधारों से इन समस्याओं को युद्धस्तर पर दूर करना होगा। जीएसटी प्रणाली में शून्य-दर वाले निर्यात का किताबी नियम व्यवहार में लाना होगा। निर्यात वृद्धि अधिक होने से आर्थिक सुस्ती दूर करने, नए रोजगार पैदा करने और हमारे बाह्य वित्त को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट व्यय के लिहाज से रह सकता है खास

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

पिछले कई वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के सालाना बजट के महत्त्व एवं इसकी उपयोगिता में ह्रास हुआ है। एक समय था जब बजट को लेकर उद्योग जगत उत्साहित रहता था और यह जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि किन उत्पादों या सेवाओं पर कर बोझ कम होगा या नए कर लगाए जाएंगे। सभी यह समझने की कोशिश करते थे कि अगले वर्ष से उन्हें प्रत्यक्ष कर से जुड़े क्या लाभ मिलेंगे। अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और व्यक्तिगत करदाताओं और कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत कर दरें अधिक स्थिर रहने से संघीय बजट का आकर्षण कम हुआ है और इसे लेकर लोगों की उत्सुकता भी पहले जैसी नहीं रह गई है।

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट कुछ अलग होगा। प्रत्यक्ष कर एवं जीएसटी दर स्थिर रहने के बावजूद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाला बजट सभी का ध्यान आकृष्ट करेगा। पिछली छह तिमाहियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर लगातार कमजोर हो रही है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए हैं, लेकिन इनका कोई सकारात्मक असर अब तक नहीं दिखा है। वित्तीय क्षेत्र भी संकट से उबर नहीं पाया है। इससे पहले कि सरकारी बैंकों को नई पूंजी देने और कई भारतीय कंपनियों द्वारा लिए ऋण के समाधान से जुड़े उपाय किए जाते, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संकट ने समस्या कई गुना और बढ़ा दी।

हाल में एक शहरी सहकारी बैंक के पतन ने वित्तीय क्षेत्र की हालत और बिगाड़ दी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस वर्ष अब तक रीपो दर 135 आधार अंक तक कम कर चुका है। हालांकि इससे ऋण आवंटन में सुधार नहीं हुआ है और न ही विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता की उपयोगिता ही बढ़ी है। बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत पार कर चुकी है, जो पिछले चार दशकों का सर्वाधिक चिंताजनक आंकड़ा है। इन कारणों से आगामी बजट पर सभी का ध्यान जाना लाजिमी है। बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ने के दो अन्य कारण भी हैं। पहला कारण तो यह है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का अनुमान काफी खुशनुमा है, लेकिन इसे प्राप्त करना सहज नहीं लग रहा है। राजस्व संग्रह के वर्तमान आंकड़ों से तो यही लगता है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। इस वर्ष के पहले आठ महीने में राजस्व संग्रह की अनुमानित दर महज 1.5 प्रतिशत रही है, जबकि लक्ष्य 18 प्रतिशत रखा गया है। दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त दूरसंचार शुल्क देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और आरबीआई से एकबारगी लाभांश से सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। हालांकि अंतर तब भी रह जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत स्तर तक रह सकता है।

दूसरा कारण यह है कि 2020-21 के बजट में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी शामिल करनी होंगी। हालांकि इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर 1 फरवरी को ही मिल पाएगा कि क्या राज्यों के साथ कर राजस्व के बंटवारे के लिए विभाज्य कोष से रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर व्यय होने वाली केंद्र की रकम के समतुल्य राशि अलग की जाएगी या नहीं। जीएसटी संग्रह की सुस्त गति से परेशान राज्यों के लिए यह दोहरी मार होगी और इससे उनका राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है।

जीएसटी संग्रह में कमी के मद्देनजर जीएसटी परिषद के समक्ष कर दरों में अधिक कटौती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसके उलट कच्चे माल की तुलना में तैयार उत्पादों पर दरें कम करने के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए जीएसटी दरें अधिक तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। तैयार उत्पादों पर दरें घटाने से कर वापसी में तेजी आई है, जिसका सीधा असर कर संग्रह पर हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स में पहले ही कमी की जा चुकी है। आरबीआई ने 1,500 कंपनियों का सर्वेक्षण किया है, जिसके अनुसार नई क्षमता विकसित करने या पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए इन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की दर में स्वागत योग्य बढ़ोतरी हुई है। आय कर दरों में कमी से लोगों के पास उपभोक्ताओं एवं निवेशकों के पास खर्च या बचत करने योग्य रकम बढ़ जाएगी। इससे देश में मांग में तेजी आने में मदद मिलनी चाहिए। वित्त मंत्रालय को प्रत्यक्ष कर समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसमें कर रियायत तर्कसंगत बनाने एवं व्यक्तिगत आयकर में कमी करने की सिफारिश की गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर व्यय की दरकार है। पिछले कुछ वर्षों में ढांचागत क्षेत्र पर व्यय घटा है और इसकी भरपाई के लिए बजट में संसाधन जुटाने की जरूरत है। अतिरिक्त संसाधन का प्रावधान करने की राह आसान नहीं होगी और इससे राजकोषीय मजबूती का निश्चय कमजोर पड़ सकता है। अगर सरकार ढांचागत क्षेत्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग सूझ-बूझ के साथ करती है तो राजकोषीय मजबूती से भटकाव को भी उचित ठहराया जा सकता है। वैसे भी जब आर्थिक वृद्धि दर पिछले 18 महीने में आधी रह गई है तो अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए राजकोषीय घाटे में इजाफा नजरअंदाज किया जा सकता है।

बजट 2020 इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि इसमें व्यय के मोर्चे पर क्या कदम उठाए जाते हैं। पिछले सप्ताह टी वी सोमनाथन को वित्त मंत्रालय में नया व्यय सचिव नियुक्त किया गया है। सोमनाथन की नियुक्ति कोई सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। वह 2015 से 2017 तक दो वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन पर नजर रखी थी। इसके बाद अगले दो वर्षों तक उन्होंने तमिलनाडु के वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग का कामकाज देखा था। अब वह केंद्र की व्यय योजना के लिए क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें होंगी।

कानाफूसी

बिगड़ती बात

जब बात देश के अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने की आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे चहेते नेताओं में से एक नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह प्रदेश में अपने खिलाफ पनप रहे असंतोष से निपटने में नाकाम रहे हैं। मंगलवार को जब भाजपा के विधायक पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा प्रताड़ना के खिलाफ विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए तो मीडिया में इसकी खबरें जमकर प्रकाशित हुईं। उधर पार्टी के एक अन्य विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के जरिये यह सुझाव दिया कि विधायकों को भी कर्मचारी संगठन जैसा एक संघ गठित करना चाहिए। उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है और इन हालात में विधायक भी खुद को असहाय पा रहे हैं। इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 40-40 विधायकों के समूह बनाकर उनसे मुलाकात करने का निश्चय किया है ताकि इन सभी समस्याओं को एकबारगी निपटाया जा सके।

आपका पक्ष

देश से पलायन रोकने के हों उपाय

प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपदा होती है। इन्हीं की दशा एवं दिशा पर देश का भविष्य निर्धारित होता है। अपने स्वर्णिम अतीत में देश इन्हीं की बहुलता के कारण स्वयं में समृद्ध एवं खुशहाल और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश था। देश-विदेश के जिज्ञासु, विद्वान एवं प्रतिभा संपन्न लोग इसी कारण यहां खिंचे चले आते थे और अपने ज्ञान को समृद्ध कर लौट जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। दूसरे देशों में प्रतिभा का पलायन कोई नई समस्या नहीं है और न ही किसी एक देश तक सीमित है। यह समस्या दशकों पुरानी है और विश्व के अधिकतर विकासशील देश इससे पीड़ित हैं। लेकिन इससे सबसे अधिक नुकसान भारत का हो रहा है, क्योंकि प्रतिभा संपन्न लोगों के क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी देश है तथा सबसे अधिक प्रतिभाओं का पलायन यहीं से हुआ है और हो रहा है। वैसे तो पहले भी

देश की प्रतिभा का पलायन रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए

प्रतिभा का पलायन होता रहा है लेकिन इस समस्या को उदारीकरण ने और हवा दी है। करीब 60 से 90 के दशकों में ज्यादातर 20-25 वर्ष की आयु की युवा प्रतिभाएं ही देश से पलायन करते थे। फ्रेशर होने के कारण इन्हें इस उम्र में दूसरे देश के वातावरण और कार्यशैली में ढलने में आसानी होती थी। दूसरा उस समय अधिकतर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ही अधिकतर जाते थे। भारत से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति विदेश पलायन कर जाते हैं जिससे भारत में उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की कमी हो जाती है। भारत से बड़े पैमाने पर डॉक्टर विदेशों में पलायन कर रहे हैं जबकि भारत में डॉक्टरों की संख्या जनसंख्या अनुपात से काफी कम है। विशेषकर भारत के गांव डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। अब वक्त आ गया है कि राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए प्रतिभाओं का पलायन रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण बनाना होगा। यह सरकार की इच्छाशक्ति एवं महत्त्व पर निर्भर करता है। सरकार को प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दे के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। देश की प्रतिभा अगर देश में ही रहकर देशहित में काम करे तो यही सबसे बेहतर होगा। इस प्रकार हम पूर्ण रूप से अपना सामाजिक विकास कर सकेंगे।

अनु मिश्रा, सीवान

विरोध प्रदर्शन में हिंसा अनुचित

नागरिकता संशोधन कानून का देश की कई जगहों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक लोग हिंसा कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग सड़कों पर आगजनी, सार्वजनिक बसों में आग लगाने, पथराव और तोड़फोड़ करने पर उतारू हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है लेकिन हिंसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। हिंसा करने से आंदोलन की दशा एवं दिशा बदल जाती है। अगर सरकार के किसी निर्णय का विरोध करना है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हिंसा से लोगों में भय पैदा होता है तथा कई लोगों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत: अपनी मांगे मनवाने के लिए देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कतई उचित नहीं है। हिंसा करने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

अभिषेक कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

पंजाब में रिकॉर्ड कपास उत्पादन की उम्मीद

पंजाब में इस वर्ष कपास उत्पादन 18 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि यह नया रिकॉर्ड होगा। सरकार ने एक बयान में कहा कि चालू सत्र में कपास उत्पादन 18.20 लाख गांठ होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष 12.23 लाख गांठ था। पिछले साल के 9.31 क्विंटल प्रति एकड़ के मुकाबले इस बार 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कपास के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए राज्य के किसानों को विशेषकर राज्य के मालवा क्षेत्र के किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कृषि विभाग को अगले खरीफ सत्र के लिए कपास उत्पादकों को समय पर अग्रिम समर्थन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अमरिंदर के पास कृषि विभाग भी है। *भाषा*

समुद्री उत्पाद निर्यात में 9 प्रतिशत गिरावट

भारत का समुद्री उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 में सालाना आधार पर नौ प्रतिशत कम होकर करीब 45 हजार करोड़ रुपये (6.30 अरब डॉलर) रह गया। समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात में 71 प्रतिशत हिस्सेदारी झींगा की रही। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। व्यापार वित्त पोषण कंपनी ड्रिप कैपिटल ने भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा है कि झींगा, फ्रोजेन फिश और घोंघा (मोलस्क) इस श्रेणी के प्रमुख उत्पाद हैं। इनमें अकेला झींगा ही भारत के कुल समुद्री उत्पाद निर्यात में 71 प्रतिशत का योगदान देता है। रिपोर्ट में विदेशी व्यापार महानिदेशालय के हवाले से कहा गया कि वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 45 हजार करोड़ रुपये का समुद्री उत्पाद निर्यात किया गया। *भाषा*

सरकारी कदम से दाल पर लगेगी लगाम

सरकारी गोदामों से माल खुले बाजार में भेजने और आयात पर बंदिश का होगा असर

सुशील मिश्र
मुंबई, 19 दिसंबर

सरकारी कवायद

- अधिसूचना के मुताबिक सभी तरह की मटर के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया
- आयात सिर्फ कोलकाता बंदरगाह से करने की अनुमति दी गई है
- इसके साथ ही सिर्फ 1.50 लाख टन मटर आयात की ही अनुमति दी गई
- भारत सबसे ज्यादा मटर आयात कनाडा से करता है

दाल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए सरकार ने दोहरे कदम उठाए हैं। एक तरफ बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकारी गोदामों से माल खुले बाजार में भेजने का फैसला किया गया है, तो दूसरी तरफ विदेशी सस्ती दाल पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दलहन आयात पर बंदिशें लगाई हैं। सबसे ज्यादा आयात की जाने वाली दलहन मटर है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक सभी तरह की मटर के लिए न्यूनतम आयात मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। आयात सिर्फ कोलकाता बंदरगाह से करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सिर्फ 1.50 लाख टन मटर आयात की ही अनुमति दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान दाल का आयात 42.65 फीसदी बढ़कर 18.73 लाख टन हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 13.13 लाख टन दलहन आयात हुआ था। भारत सबसे ज्यादा मटर आयात कनाडा से करता है। फिलहाल आयातित मटर का भाव 5,100 रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास है, जबकि घरेलू बाजार में मटर की कीमत 80 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है।

सरकार के इस फैसले पर दलहन कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने एक तरह से मटर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उड़द आयात की सीमा डेढ़ लाख टन पहले से ही तय कर रखी है। 5.75 लाख टन अरहर आयात (चार लाख टन निजी आयात से और 1.75 लाख टन सरकारी अनुमति से) की अनुमति है। चना आयात पर 60 फीसदी और मटर आयात पर 30 फीसदी आयात शुल्क तय किया गया है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार दलहन कारोबार पर बंदिश लगा रही है जिस कारण कारोबार बढ़ नहीं पा रहा है। सरकार सोचती है कि उसके इस कदम से किसानों को फायदा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बाजार खुले मंच की तरह हो तो उसका फायदा ग्राहकों को होता है।

आयात पर बंदिशों के साथ ही सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से लगभग साढ़े आठ लाख टन दलहन बाजार में लाने का फैसला किया है। केंद्र राज्यों को बाजार मूल्य पर दलहन उपलब्ध कराएगा। प्रमुख शहरों में दाल का भाव औसतन 60 रुपये से 95 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। कुछ जगह उड़द 140 रुपये तक चली गई है। सरकारी बयान में कहा गया है कि मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बफर स्टॉक से औसत बाजार दर पर राज्य सरकारों को 8.47 लाख टन दलहन बिक्री की पेशकश की है।

सरकार ने 3.2 लाख टन अरहर, दो लाख टन उड़द, 1.2 लाख टन चना, 1.5 लाख टन मूंग और 57,000 टन मसूर की पेशकश की है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चने की औसत दर 65 रुपये प्रति किलोग्राम, अरहर 85 रुपये प्रति किलोग्राम, उड़द 95 रुपये प्रति किलोग्राम, मूंग 85 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। हालांकि चने की अधिकतम दर 88 रुपये, अरहर की 110 रुपये, उड़द की 140 रुपये, मूंग की 120 रुपये और मसूर की अधिकतम दर 100 रुपये प्रति किलोग्राम है।

भारतीय दलहन एवं अनाज संघ (आईपीजीए) के अध्यक्ष जीतू भेड़ा ने कहा कि आईपीजीए इसका स्वागत करता है, लेकिन केवल उड़द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊंचे भाव पर बिक रही है। केवल इसे ही बफर स्टॉक से जारी किया जाना चाहिए। अन्य सभी दालें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं और इसलिए इनका बफर स्टॉक खाली नहीं किया जाना चाहिए। भेड़ा ने कहा कि सरकार को उड़द के लिए आयात मानदंडों में ढील देने पर विचार करना चाहिए।

आईटीए ने चाय बोर्ड से किया संपर्क

चाय बागान में पाम तेल उत्पादन की मांग

अभिषेक रक्षित
मुंबई, 19 दिसंबर

- भारत पाम तेल का शुद्ध आयातक है जो 25,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आयात करता है
- भारत सरकार चाय उत्पादकों को पाम के तेल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सकती है

भारतीय चाय संघ (आईटीए) ने चाय बागान की जमीन पर पाम तेल उत्पादन के लिए चाय बागान कंपनियों को अनुमति दी जाने के लिए भारतीय चाय बोर्ड से संपर्क किया है। आईटीए के चेयरमैन विवेक गोयनका ने कहा, 'हमने चाय बोर्ड से इस बात पर विचार करने के लिए निवेदन किया कि क्या हम अपने बागान में पाम की खेती और पाम तेल का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें बड़े इलाके की जरूरत है।' गोयनका के अनुसार जमीन का इस्तेमाल राज्य का विषय है और संबंधित राज्य इस बात का फैसला कर सकते हैं कि चाय की खेती वाली जमीन का इस्तेमाल कैसे किया जाए।

पश्चिम बंगाल जैसे चाय की खेती करने वाले राज्य पहले ही चाय बागान की जमीन का इस्तेमाल चाय से अलग उद्देश्य के लिए मंजूरी दे चुके हैं और असम से उम्मीद की जा रही है कि वह इसका अनुसरण करेगा। गोयनका ने कहा कि इससे उद्योग को बहुत फायदा होगा क्योंकि भारत पाम तेल का शुद्ध आयातक है जो 25,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आयात करता है।

आईटीए ने कहा कि मलेशिया चाय उत्पादकों को चाय से हटकर पाम के तेल का उत्पादन करने की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तथा भारत सरकार भी चाय उत्पादकों को पाम के तेल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब चाय उद्योग चाय के कम लाभकारी दामों की शिकायत कर रहा है। इससे सभी प्रमुख चाय कंपनियों की बैलेंस शीट प्रभावित हो रही है और कुछ कंपनियां जमीन के वैकल्पिक इस्तेमाल का दबाव डाल रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 19	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,758.0	-0.3	1,914.4	-3.2
Copper	6,126.5	6.4	6,418.9	3.8
Nickel	13,850.0	-19.8	14,498.9	-18.6
Lead	1,872.0	-10.0	2,224.1	7.2
Tin	17,250.0	4.4	18,088.4	0.8
Zinc	2,307.0	0.3	2,604.2	0.4
Gold ($/ounce)	1,474.6*	-1.6	1,658.4	1.5
Silver ($/ounce)	17.0*	-4.7	19.3	-3.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	67.8*	4.7	66.8	4.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.2*	-11.8	2.3	-11.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	189.0	11.0	302.8	6.4
Maize	182.1*	0.9	332.9	13.6
Sugar	356.8*	10.8	487.2	-0.5
Palm oil	720.0	34.6	1,126.1	29.6
Rubber	1,584.8*	0.7	1,844.0	2.0
Coffee Robusta	1,365.0*	6.4	1,872.2	-9.2
Cotton	1,480.2	13.8	1,586.5	-2.9

* As on Dec 19, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	52.1	12267
Oil and Oilseeds	266.4	81422
Spices	1.4	15
Metal(Dec 18)		
Metal- non ferrous	5264.0	60569
Metal- precious	7592.7	444
Oil and gas(Dec 18)		
Gas	2400.3	45530
Oil	14328.5	3421

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	187.0	104286
Grains	321.5	98880
Oil and Oilseeds	891.7	499210
Others	151.1	68775
Pulses	133.6	52050
Spices	81.1	30315

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Kapas (Apr 30)	1105.5	1.1
Lead (Dec 31)	153.4	0.5
Zinc (Dec 31)	183.5	0.5
Lead Mini (Dec 31)	153.4	0.5
Cotton (Dec 31)	19160.0	0.5
Aluminium (Dec 31)	133.8	0.5
Losers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3260.4	-3.7
Natural Gas (Dec 26)	162.1	-1.9
Mentha Oil (Dec 31)	1295.3	-0.9
Nickel (Dec 31)	1011.7	-0.9
Silver Mini (Feb 28)	44466.0	-0.2
Silver Micro (Feb 28)	44467.0	-0.2

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Guar Seed 10 (Dec 20)	4154.0	3.0
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2092.0	1.8
Coriander-Kota (Dec 20)	6980.0	1.2
Soyabean Indore (Dec 20)	4302.0	1.1
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7500.0	1.0
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4358.0	1.0
Jeera Unjha (Jan 20)	16020.0	1.0
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1106.0	1.0
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	885.6	0.6
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6256.0	0.3
Chana-Bikaner (Dec 20)	4441.0	0.2
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4525.0	0.1

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3260.4	3.1
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19160.0	2.2
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3856.0	1.4
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44467.0	1.1
Silver Ahm (Mar 05)	44447.0	1.1
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	1.0
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1295.3	-7.8
Aluminium Mum (Dec 31)	133.8	-3.7
Alumini-Mumbai (Dec 31)	133.8	-3.7
Copper Mum (Dec 31)	443.7	-3.5
Nickel Mumbai (Dec 31)	1011.7	-2.6
Lead Mum (Dec 31)	153.4	-0.9

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6256.0	3.4
Coriander-Kota (Dec 20)	6980.0	1.4
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	736.9	0.3
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7500.0	0.3
Barley Jaipur (Dec 20)	2131.0	0.1
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18740.0	0.1
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3201.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Jeera Unjha (Jan 20)	16020.0	-2.0
Soy Bean Indore (Dec 20)	4302.0	-1.1
Moong-Merta City (Dec 20)	6825.0	-1.1
Maize-Sangli (Dec 20)	2084.0	-0.8

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98(98)
Aluminium ingots /kg	136(135)
Brass sheet cutting /kg	320(320)
Brass utensil scraps/kg	306(306)
Copper heavy scrap /kg	424(425)
Copper utensil scraps/kg	398(400)
Copper wire bar /kg	456(458)
Lead ingots /kg	158(158)
Nickel Cathodes /kg	1030(1035)
Tin slabs /kg	1285(1290)
Zinc slabs /kg	185(184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10714(10742)
DCH - 32 /Qtl	11220(11276)
Jaydhar /Qtl	10039(10067)
Shankar- 6 /Qtl	11023(11079)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	925(914)
Castor Comm /10kg	915(904)
Ricebran oil/10kg	760(760)
Groundnut oil /10kg	1120(1120)
Linseed oil /10kg	900(895)
Karanji /10kg	780(780)
Palm oil /10kg	795(806)
Sunflower exp ref /10kg	875(875)
Sunflower oil exp /10kg	845(840)
Soyabean ref / 10kg	870(870)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3332-3590 (3372-3596)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	60.94(60.93)
Brent Crude (UK)	67.79(67.79)
Brent Crude (WTI)	60.93(60.93)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.27(2.29)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	280.61(274.55)
Naptha spot /Rs/MT	45170(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37877(37959)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38029(38112)
Silver.999/ kg	43975(44200)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18727.10	18718.25
Alumini-Mumbai (M)	1 K	139.50	138.95
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2050.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2130.00	2128.00
Brass-Jamnagar (M)	1 K	317.30	312.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3300.00	3233.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4394.15	4422.70
Castor Seed-Kadi (N)	X	4325.00	4355.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4350.00	4367.75
Chana Delhi (N)	1 Q	4538.05	4562.50
Chana-Akola (N)	X	4380.00	4450.00
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6550.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6900.00	6932.50
Coriander-Kota (N)	1 Q	6885.40	6883.60
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2100.00	2120.10
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2088.90	2122.90
Cotton-Kadi (N)	1 B	18611.70	18644.55
CPO-Kandla (M)	10 K	729.80	730.80
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	735.35	734.40
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	884.35	889.10
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1534.30	1540.35
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3440.20	3445.40
Gold Ahm (M)	10 G	37955.00	37882.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30486.00	30427.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3810.00	3801.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7470.00	7478.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4034.60	4046.50
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3993.00	3988.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1188.65	1196.45
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	94.10	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16800.00	16600.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16354.55	16354.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1031.45	1036.40
Kapas-Rajkot (N)	X	1028.85	1033.95
Lead Mum (M)	1 K	154.80	154.85
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2060.00	2075.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2363.95	2367.10
Maize-Erode (N)	X	2077.10	2082.50
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Maize-Sangli (N)	X	2083.35	2100.45
Moong-Merta City (N)	1 Q	6822.20	6900.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4733.15	4694.50
Nickel Mumbai (M)	1 K	1033.20	1039.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3135.00	3171.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	355.00	356.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35775.00	35766.65
Rape mustards-Patan (I)	20 K	822.00	829.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2044.40	2042.20
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	797.75	800.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	879.95	883.30
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	870.00	871.40
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	892.50	893.75
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13200.00	13121.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44183.00	43978.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4339.00	4350.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4242.00	4254.65
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4343.00	4393.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4330.00	4353.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35240.00	35256.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	881.00	878.40
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	28270.00	28520.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29200.00	29300.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26530.00	26840.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3314.30	3323.80
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3271.65	3281.45
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3428.55	3433.35
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3261.90	3250.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3134.50	3129.10
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6036.35	6047.75
Wheat Delhi (N)	1 Q	2266.65	2270.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2150.00	2147.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2235.00	2225.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2085.00	2080.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2185.00	2200.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4937.25	4937.25
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.35	184.60

* as on Dec 18, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19060, 19190, 19040, 19160	2929	475	6025
Jan 31	19280, 19400, 19270, 19370	1535	262	5285
Feb 28	19500, 19590, 19500, 19540	34	5	340
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2055, 2116, 2055, 2092	190	18	2530
Jan 20	2063, 2133, 2053, 2127	57690	3766	63100
Feb 20	2077, 2152, 2076, 2147	15220	1247	31450
Mar 20	2104, 2167, 2104, 2166	990	92	3000
Apr 20	2167, 2185, 2164, 2185	30	3	130
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1092, 1105.5, 1091, 1105.5	236	47	584
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1092.5, 1107, 1091.5, 1106	1402	787	4076
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4096, 4154, 4096, 4154	105	7	275
Jan 20	4096, 4202, 4088, 4176	62285	6381	81945
Feb 20	4138, 4248, 4130, 4222	15035	1661	14750
Mar 20	4208, 4232, 4208, 4232	20	4	60
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4320, 4370, 4304, 4358	520	64	1550
Jan 20	4344, 4394, 4332, 4382	5820	645	29585
Feb 20	4360, 4412, 4352, 4402	775	111	4640
Mar 20	4374, 4392, 4366, 4380	315	48	5070
Apr 20	4350, 4376, 4350, 4362	195	35	180
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	725.2, 732.5, 722, 731.2	10710	829	24960
Jan 31	729, 738.6, 725, 737.1	18510	1257	47750
Feb 28	728.8, 741.6, 727, 740.9	3410	270	8370
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1307.9, 1310.5, 1292.5, 1295.3	170.28	393	240.84
Jan 31	1316, 1317, 1301.1, 1304.1	46.8	123	100.8
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4545, 4545, 4497, 4525	30	3	20
Jan 20	4544, 4592, 4538, 4586	10450	799	19540
Feb 20	4510, 4565, 4500, 4548	560	46	1830
Apr 20	4445, 4514, 4440, 4507	4870	349	6920
May 20	4460, 4508, 4460, 4475	370	15	320
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	881, 886, 878.8, 885.6	2115	132	6500
Jan 20	885.8, 901.4, 882.8, 898.4	33825	3509	55310
Feb 20	877, 893.2, 877, 890.4	16950	1438	35725
Mar 20	870.2, 882, 870, 880.4	1470	177	1395
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4260, 4310, 4250, 4302	680	88	890
Jan 20	4306, 4356, 4272, 4344	51165	5505	161890
Feb 20	4326, 4382, 4304, 4376	13530	1915	126140
Mar 20	4360, 4414, 4338, 4408	3055	487	38450
Apr 20	4392, 4452, 4392, 4448	1090	182	3255
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7500, 7500, 7500, 7500	220	11	140
Jan 20	7425, 7631, 7400, 7584	15400	2230	58295
Feb 20	7530, 7744, 7499, 7693	4415	687	10220
Mar 20	-, 7629, -, 7629	10	1	120
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4440, 4460, 4340, 4441	340	28	960
Jan 20	4438, 4488, 4438, 4480	26720	1952	46210
Mar 20	4400, 4428, 4378, 4418	2700	233	4360
Apr 20	4371, 4400, 4371, 4395	190	10	450
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3440, 3440, 3251.6, 3260.4	3.7	29	11.1
Feb 14	3132.1, 3132.1, 3100, 3120.7	0.6	6	3.3
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6980, 7000, 6911, 6980	810	55	2810
Jan 20	6354, 6440, 6340, 6383	2660	169	9480
Apr 20	6780, 6849, 6777, 6828	990	93	4900
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15895, 16045, 15720, 16020	2013	581	2349
Mar 20	15600, 15705, 15455, 15665	126	41	312
Apr 20	15400, 15400, 15400, 15400	6	2	39
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6246, 6260, 6150, 6256	740	32	390
Mar 20	6266, 6292, 6170, 6246	1560	215	7180
Apr 20	6114, 6154, 6060, 6138	550	99	2840
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.8, 134.2, 133.6, 134.1	2550	446	8195
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.7, 134.15, 133.55, 134.1	1518	1263	3023
Jan 31	134.3, 134.75, 134.15, 134.75	187	173	1141
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	442.6, 444, 441.7, 443.45	13535	4572	14585
Jan 31	447.3, 448.9, 446.7, 448.75	925	336	3050
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.7, 153.75, 153.15, 153.4	4835	798	4725
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.6, 153.7, 153.2, 153.4	2453	2071	2146
Jan 31	152.35, 152.45, 152.1, 152.35	348	297	2200

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1012.5, 1020.7, 1011, 1018.4	10683	6327	2941.5
Jan 31	1011.8, 1022.8, 1009.3, 1020	559.5	360	523.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.65, 183.7, 183.05, 183.35	13425	2209	14680
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183.4, 183.5, 182.85, 183.1	4310	3411	5896
Jan 31	182.45, 182.6, 181.85, 182.4	1352	843	8398
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37959, 37977, 37860, 37883	5	4094	16.04
Apr 03	38001, 38020, 37920, 37962	0.37	308	3.71
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30534, 30540, 30515, 30524	0	87	0
Jan 31	30474, 30480, 30407, 30438	0	49	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37998, 37998, 37880, 37896	0.49	4129	0.83
Feb 05	37950, 37983, 37880, 37897	0.1	871	0.3
Mar 05	37936, 37936, 37890, 37915	0	6	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3856, 3856, 3846, 3852	0	436	0.01
Jan 31	3844, 3853, 3830, 3838	0	117	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44511, 44630, 44263, 44296	201.24	5421	387.6
May 05	44975, 44975, 44787, 44807	1.02	32	6.48
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44475, 44600, 44302, 44334	20.32	13866	33.45
Apr 30	45000, 45068, 44805, 44830	0.69	567	1.92
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44507, 44596, 44295, 44324	66.63	10577	59.21
Apr 30	45068, 45068, 44799, 44824	0.63	119	2.01
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	162.9, 162.9, 160.6, 161.2	47910mb	23126	33906mb
Jan 28	162, 162.9, 160.5, 161	6740mb	3551	16823mb
Feb 25	159.5, 160.1, 158.1, 158.4	443mb	341	3990mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4324, 4342, 4318, 4336	6306bl	37239	3869bl
Feb 19	4320, 4338, 4313, 4332	94bl	815	53bl
सायं सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19140, 19150, 19000, 19060	2577	455	6790
Jan 31	19350, 19360, 19240, 19270	2011	337	4634
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1099, 1100, 1091, 1093.5	244	57	544
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1098.5, 1100, 1091, 1093.5	1226	650	4028
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	735, 737.9, 725.9, 727.8	13880	1138	25060
Jan 31	735.5, 739.2, 728.4, 730.8	23400	1597	48060
Feb 28	732.2, 738.5, 728.5, 731.8	4020	313	6680
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	878.8, 881.6, 875.6, 878.8	1015	88	6605
Jan 20	888, 891.8, 881.6, 884.2	34340	3850	48985
Feb 20	874.4, 883.8, 873, 877.8	8400	844	30445
Mar 20	868.2, 873, 868.2, 872	175	26	525
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.3, 133.95, 133.3, 133.75	8770	1313	7720
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.35, 133.95, 133.35, 133.8	2846	2319	2686
Jan 31	134.15, 134.4, 133.95, 134.3	403	276	1054
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	443.6, 444.15, 441, 443.7	29465	9788	12460
Jan 31	448.1, 449, 446.1, 448.6	1222.5	458	2727.5
Feb 28	451.35, 451.7, 451.35, 451.5	27.5	11	57.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.4, 153.6, 152.25, 153.4	18840	2916	4110
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.65, 153.55, 152.4, 153.4	6656	5336	1693
Jan 31	152.15, 152.3, 151.85, 152.1	1081	660	2157
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1020, 1021, 1009, 1011.7	22569	13261	1488
Jan 31	1014, 1014.7, 1006.9, 1009.2	598.5	384	408
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.6, 184.5, 182.8, 183.5	38805	6065	11145
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183, 183.8, 182.55, 183.25	12410	9259	4644
Jan 31	181.3, 182.35, 181, 182.15	2822	1808	8184
Feb 28	181.5, 182, 181.3, 181.6	3	3	26
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37959, 37995, 37802, 37912	10.14	8446	15.36
Apr 03	38015, 38059, 37864, 37970	0.52	424	3.52
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30512, 30544, 30492, 30512	0	161	0
Jan 31	30459, 30524, 30406, 30460	0	119	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37937, 37994, 37817, 37932	1.21	10212	0.75
Feb 05	37950, 37996, 37825, 37926	0.25	2084	0.28
Mar 05	37906, 38003, 37850, 37937	0	43	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3854, 3858, 3852, 3856	0	774	0.01
Jan 31	3839, 3845, 3835, 3837	0	305	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44447, 44589, 44180, 44447	483.48	13102	342.09
May 05	44979, 45056, 44672, 44861	2.7	81	6.78
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44480, 44606, 44205, 44467	43.23	29069	28.01
Apr 30	44954, 45065, 44713, 44945	1.91	1439	1.82
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44351, 44600, 44203, 44466	141.63	22197	43.42
Apr 30	44988, 45067, 44710, 44946	1.67	293	1.95
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	165.5, 165.8, 160.8, 162.1	132740mb	59607	26048mb
Jan 28	164.5, 165.6, 160.9, 161.4	13423mb	6913	15583mb
Feb 25	161.8, 162.1, 158.4, 158.7	1353mb	965	3900mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4317, 4374, 4285, 4330	21765bl	106436	695bl
Jan 17	4319, 4347, 4290, 4344	6764bl	39967	2398bl
Feb 19	4305, 4340, 4283, 4338	114bl	894	37bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4312, 4354, 4285, 4330	4557bl	166838	291bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

नागरिकता कानून का देश भर में विरोध

बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंसक विरोध-प्रदर्शन, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकियां जलाईं

बीएस संवाददाता

देश के विभिन्न हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को व्यापक प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंसा तथा आगजनी भी देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर लगी रोक के बावजूद गुरुवार को सड़कों पर उतरने के चलते सैकड़ों छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया।

लखनऊ में जबरदस्त बवाल हुआ। यहां तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कई जगहों पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जमा हुए, जुलूस निकाला, जमकर नारेबाजी की और तांडव मचाया। पूरे शहर में कई जगहों पर हिंसा फैली। राजधानी के पास हजरतगंज इलाके में घंटों प्रदर्शनकारी बवाल करते रहे और पुलिस से उलझते रहे। ठाकुरगंज में सतखंडा चौकी फूंक दी गई, चौकी में खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई, मदेयगंज के बाद सतखंडा चौकी फूंकी गई। दर्जनों मीडियाकर्मी भीड़ के हमले और पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं और कुछ टीवी चैनलों की ओबी वैन भी तोड़ी गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, शाहनवाज आलम कई अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

बेकाबू हालात को संभालने के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को सड़कों पर उतरना पड़ा। प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए और कुछ जगहों पर हिंसा की खबर है। संभल में उपद्रवियों ने बस फूंक दी। लखनऊ के बिगड़े हालात के मद्देनजर सरकार ने शाम को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी जताई। राजधानी लखनऊ में कई सामाजिक संगठनों की ओर से परिवर्तन चौक पर गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रतिरोध मार्च का आह्वान किया गया था। मार्च के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस ने बड़े पौमाने पर नाकेबंदी का ऐलान करते हुए किसी को भी उस ओर न जाने की चेतावनी जारी की थी। गुरुवार सुबह से पुलिस की सारी व्यवस्था नाकाम साबित हुई और राजधानी से तमाम इलाकों से लोग टुकड़ों टुकड़ों में परिवर्तन चौक पहुंचने लगे। दोपहर दो बजे तक परिवर्तन चौक पर हजारों लोग पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। राजधानी के कई और इलाकों में भी अलग-अलग प्रदर्शन शुरू हो गया।

लखनऊ में समाजवादी पार्टी का भी विरोध प्रदर्शन हुआ। पुराने लखनऊ के खदरा इलाके में हिंसा की घटना में थाना हसनगंज के मदेहगंज पुलिस चौकी पर आग लगाई गई व पुलिस के कई वाहन फूंक दिए गए। पुराने लखनऊ से परिवर्तन चौक की ओर बढ़ रही सैकड़ों लोगों को पुलिस ने रोका और छोटे इमामबाड़े पर जबरदस्त प्रदर्शन के बीच लाठीचार्ज, पथराव हुआ। परिवर्तन चौक पर भीड़ को तितरबितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लखनऊ में सभी मेट्रो स्टेशन बंद किए गए जिससे यात्री फंस गए। पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि स्थिति काबू में है और घबराने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने उपद्रव किया, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है।

लखनऊ में परिवर्तन चौक पर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों पर पथराव करते हुए फोटो : पीटीआई

वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। कई मेट्रो स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया, जिससे शहर में यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि देर शाम तक मेट्रो स्टेशनों को खोल दिया गया। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार इंटरनेट सेवा बंद करने और निषेधाज्ञा लगाने जैसे दमनकारी कदमों से लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और देश में अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस ने कहा, 'लेकिन सरकार जितना आवाज दबाएगी, उतनी तेज आवाज उठेगी और देश में शांति तभी आएगी, जब इस सरकार को बताया जाएगा कि इनका देश से जाने का समय आ गया है।'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए और यदि वह व्यापक मत हासिल करने में विफल रहती है तो उसे सत्ता छोड़नी होगी।

पृष्ठ 1 का शेष

राजनीतिक दलों ने भी किया प्रदर्शन

कर्नाटक के हुबली, कलबुर्गी, हासन, मैसूरु और बेल्लारी सहित तमाम हिस्सों में प्रदर्शन हुए। पुलिस ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया। नामी कंपनी बायोकॉन की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने पुलिस की कार्रवाई पर आश्चर्य जताया है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने लोगों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोगी की अपील की। मुंबई में भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पुणे और नागपुर में भी किए गए। कोलकाता में हुई विशाल रैली में विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन, अभिनेताओं कौशिक सेन और ऋद्धि सेन ने भी विरोध में निकले जुलूस में हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान कुछ इलाकों में मैसेज सेवाएं बाधित रहीं। मैसेज सेवाओं को बंद करने का आदेश दिल्ली पुलिस ने दिया था।

भाजपा-कांग्रेस से अलग राह पर शिवसेना

सुशील मिश्र

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर शिवसेना एक तरफ भाजपा पर हमलावार है, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ न खड़े होकर अपनी अलग राह तैयार करने में जुटी है। केंद्र सरकार पर हमला करके शिवसेना अपने सहयोगियों को खुश करने और सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल न होकर अपने हिंदुत्व के चेहरे को भी बचाकर रखने की चाल चल रही है। शिवसेना की नई चाल से भाजपा और कांग्रेस दोनों हैरान लग रहे हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भाजपा पर निशाना साधते कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि अन्य देशों से आने वाले हिंदुओं को कहां और कैसे बसाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके (केंद्र) पास इस संबंध में कोई भी योजना है। गौरतलब है कि ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन राज्यसभा में इस पर मतदान के दौरान सदन से बर्हिगमन कर गए थे। उनका आरोप था कि पार्टी को उसके सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

मुंबई में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित आंदोलन में शिवसेना शामिल नहीं हुई। इस बारे में जब मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ से पूछा गया कि शिवसेना 'हम भारत के लोग' नामक मोर्चे का हिस्सा क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन गैर-सरकारी संगठनों ने आयोजित किया है, उनकी पार्टी ने नहीं। गायकवाड़ ने कहा कि नागरिक समूहों ने कांग्रेस, राकांपा और अन्य पार्टियों को प्रदर्शन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अगर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन आयोजित किया होता तो हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सभी साझेदारों को आमंत्रित करते। 'हम भारत के लोग' मोर्चे के सदस्य फिरोज मीटीबोरवाला ने कहा, 'हमने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए नागरिक समूहों को साथ लेकर अखिल भारतीय मंच बनाया है। हम शिवसेना को मंच में शामिल करने को लेकर उसके साथ संपर्क में हैं। उद्धव जी ने आज अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के लिए हमारी मदद की है।' इससे पहले हम भारत के लोग मोर्चे की ओर से जारी एक विज्ञप्ति जारी कर सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक तथा भेदभावपूर्ण करार दिया।

शिवसेना के रुख पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे को कठपुतली मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि उन्हें कोई भी निर्णय लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राकांपा सुप्रीमो शरद पवार की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए वह सदन में हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं।

बाजार की तेजी एक पहेली: सुब्रमण्यन

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने इस बात पर हैरानी जताई है कि शेयर बाजार कैसे चढ़ रहा है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। सुब्रमण्यन ने कहा कि उनके लिए यह पहेली है कि शेयर बाजार कैसे चढ़ रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यन ने गुरुवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए) में एनएसई सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंस इन फाइनैंस, इकनॉमिक्स ऐंड मार्केटिंग के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इस केंद्र के अर्थशास्त्र के बर्ताव पर पहली परियोजना से मुझे इस सवाल का जवाब मिल सकेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था नीचे और नीचे और शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा है।'

सुब्रमण्यन ने कहा, 'यदि आप मेरे लिए इस पहेली को सुलझा सकते हैं तो मैं अमेरिका से सीधे यहां ाआऊंगा....इसके अलावा कई और चीजें मुझे समझ नहीं आती हैं जैसे भारत के वित्तीय बाजार।' सुब्रमण्यन ने हाल में कहा था कि भारत गहरी मंदी की ओर जा रहा है। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स गुरुवार को 115.35 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 41,673.92 अंक पर बंद हुआ। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 38.05 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 12,259.70 अंक के नए उच्चस्तर पर बंद हुआ। आईआईएमए के निदेशक प्रो. एरोल डीसूजा ने अपने संबोधन में कहा कि आईआईएमए के परिसर में जिस नए केंद्र का उद्घाटन किया गया है, वह इस बात पर प्रयोग करेगा कि कैसे व्यावहारिक विज्ञान के अलग-अलग पहलू बाजारों में प्रक्रियाओं और परिणामों को प्रभावित करते हैं। *एजेंसियां*

पृष्ठ 1 का शेष

सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन कूल्टर नाइल को मुंबई इंडियंस ने आठ करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा, जबकि आस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज अलेक्स कैरी को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को आईपीएल के पहले सत्र की विजेता राजस्थान रॉयल्स ने तीन करोड़ रुपये में खरीदा। वह इस नीलामी में डेढ़ करोड़ रुपये की मूल कीमत के साथ शामिल हुए थे। भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को इस नीलामी में काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2018 में 11.5 करोड़ रुपये और 2019 में 8.5 करोड़ रुपये की बोली पाने वाले इस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्य ने केवल तीन करोड़ रुपये में अपने टीम में शामिल किया।आईपीएल टीम मालिकों ने युवा खिलाड़ियों के लिए भी खजाने खोल दिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने झारखंड के बल्लेबाज विराट सिंह और भारतीय अंडर-19 टीम के मौजूदा कप्तान प्रियम गर्ग को 1.90 करोड़-1.90 करोड़ रुपये में खरीदा जबकि भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को कोलकाता नाइट राइडर्स ने चार करोड़ रुपये में टीम से जोड़ा। भारतीय अंडर-19 टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.40 करोड़ रुपये में खरीदा।

जीवन बीमा में महिलाओं की 36 प्रतिशत हिस्सेदारी

सुब्रत पांडा

देश की आबादी में भले ही महिलाओं की 48 प्रतिशत हिस्सेदारी हो लेकिन जीवन बीमा योजनाओं में उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। साल 2018-19 के दौरान कुल 2.86 करोड़ जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी गईं जिसमें से महिलाओं ने 1.03 करोड़ पॉलिसी खरीदीं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

इस बार कुल पॉलिसी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत रही जो साल 2017-18 में 32 प्रतिशत ही थी। इसी तरह, पहले साल के प्रीमियम के तौर पर 2018-19 में महिलाओं ने कुल राशि का 37 प्रतिशत भुगतान किया, जो 2017-18 में 32 प्रतिशत था। निजी कंपनियों द्वारा दी जाने वाली जीवन बीमा पॉलिसी में महिलाओं की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत रही जबकि एलआईसी की पॉलिसी में यह 39 प्रतिशत रही। अर्थात, महिलाओं ने निजी कंपनियों के मुकाबले एलआईसी को अधिक वरीयता दी।

वर्ष 2018-19 में कुल 2.86 करोड़ जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी गईं जिनके एवज में बीमा धारकों ने कुल 97,690 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया। इसके अलावा, छह लाख से अधिक महिलाएं जीवन बीमा उद्योग में एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं और मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या कुल मानव श्रम बल का 27.5 प्रतिशत है। इस कुल संख्या में निजी जीवन बीमा कंपनियों का अनुपात 52 प्रतिशत और एलआईसी का 48 प्रतिशत है।

निजी जीवन बीमा कंपनियों में से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सबसे अधिक करीब 45 प्रतिशत महिला एजेंट हैं और इसके बाद आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस तथा स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस का स्थान है।

44 सूचीबद्ध कंपनियों के सीएसआर में गाय भी शामिल

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाए हो चुके हैं पांच साल

सचिन मामबटा

बॉम्बे पंजरापोल और उसके नीले रंग के ऊंचे प्रवेशद्वार तक जाने वाली संकरी गलियां इसके भीतर दो एकड़ में फैली गौशाला से बिल्कुल विपरीत हैं। देश की वित्तीय राजधानी के बीचोंबीच स्थित इस गौशाला में 350 गाय हैं। ऐसे शहर, जिसमें वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 500 वर्ग फुट का अपार्टमेंट खरीदना भी बड़ा मुश्किल है, वहां ऐसी गौशालाओं की संख्या बढ़ रही है। इसका श्रेय भारतीय कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले धन को जाता है, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय कंपनियों का गौशालाओं को दान देने में रुझान बढ़ रहा है।

मुंबई में फ्लोर स्पेस इंडेक्स 1.83 है, इसलिए दो एकड़ के भूखंड में 500-500 वर्ग फुट के कम से कम 320 अपार्टमेंट बन सकते हैं। कॉरपोरेट ट्रैकर एनएसईइन्फोबेस डॉट कॉम के आंकड़े दर्शाते हैं कि कम से कम 21 सूचीबद्ध कंपनियों ने 2018-19 में अनिवार्य कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च के तहत गाय एवं संबंधित पहलों के लिए धन मुहैया कराया है। सीएसआर खर्च शुरू होने के बाद ऐसे ऐसे दान देने वाली सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर को अनिवार्य बनाए हुए पांच साल हो गए हैं।

जिन परियोजनाओं में गाय एवं संबंधित गतिविधियां शामिल हैं, उनका सालाना खर्च बढ़कर 12.6 करोड़ रुपये हुआ

उन परियोजनाओं पर कुल सालाना खर्च बढ़कर 12.6 करोड़ रुपये हो गया है, जिनमें गायों से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं। यह धनराशि वित्त वर्ष 2018 में 9.11 करोड़ रुपये थी। इसमें वित्त वर्ष 2019 के दौरान 38.7 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। यह राशि एक साल में 50,000 स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक राशि के बराबर है। सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के आंकड़ों के अनुमानों के मुताबिक प्रत्येक भोजन की लागत 7 रुपये से कम है। प्राइम की एनएसईइन्फोबेस डॉट कॉम के आंकड़े दर्शाते हैं कि गाय से संबंधित कार्यों पर खर्च इस साल सबसे अधिक रहा है। हालांकि अलग से आंकड़ों के अभाव में यह पता लगाना मुश्किल है कि केवल गाय से संबंधित परियोजनाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ है।

कॉरपोरेट ट्रैकर प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्दिया ने कहा, 'मौजूदा सरकार की इस विषय में रुचि को देखते हुए गौशालाओं को कंपनियों द्वारा धन दिया जाना कोई अचंभा नहीं है। हालांकि कुल सीएसआर खर्च में गौशाला परियोजनाओं पर खर्च होने वाली धनराशि का हिस्सा छोटा है।'

उदाहरण के लिए कुछ खर्च मिश्रित परियोजनाओं के जरिये किए गए हैं। इन मिश्रित परियोजनाओं में गौशालाओं के अलावा कृषि बुनियादी ढांचे का सृजन, जल संसाधन प्रबंधन एवं अन्य पहल आदि शामिल हैं। कुछ अन्य इन मदों पर खर्च होने वाली राशि को सीधे 'गौशाला' और 'गौशालाओं के लिए भुगतान' में दिखाते हैं। कंपनियों ने ग्रामीण विकास और पशुपालन के लिए विभिन्न प्रावधानों के तहत आवंटन किया है। सीएसआर के तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर लैंगिक समानता जैसे कार्यों के लिए धन दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया के संस्थापक और प्रबंध निदेशक अमित टंडन ने कहा कि कुछ मामलों में खर्च का कंपनी के परिचालन से भी संबंध हो सकता है। उन्होंने कहा, 'जब इसका कंपनी के कारोबार से संबंध होता है तो इसे भागीदारों के बीच ज्यादा स्वीकार्यता मिलती है।'

पराग मिल्क फूड्स ने पशु शेल्टर के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक राशि दान दी है, जिसमें पशुओं की देखभाल की जाती है। कंपनी इस शेल्टर के लिए लगातार दो साल से योगदान दे रही है। कंपनी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

हालांकि इस तरह का तालमेल सभी कंपनियों में स्पष्ट नजर नहीं आता है। फेविकोल ब्रांड की मालिक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज गौशाला समेत कई परियोजनाओं पर 9.3 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जेनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भी गाय संरक्षण एवं पशु कल्याण गतिविधि कार्यक्रमों और पक्षियों एवं गायों को चारा एवं छांव मुहैया कराने के लिए 20 लाख रुपये से अधिक का दान दिया है।

क्षेत्रीय चैनलों पर दांव लगा रही ज़ी एंटरटेनमेंट

विवेट सुजन पिंटो और सोहिनी दास

मनोरंजन एवं मीडिया क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट ने पिछले तीन वर्षों में दर्शक संख्या बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय चैनलों पर दांव लगाया है। कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी (घरेलू कारोबार) पुनीत मिश्रा ने एक बातचीत में बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि ज़ी को होने वाली कमाई का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय चैनलों से आता है। उन्होंने कंपनी को इस श्रेणी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया।

मिश्रा बताते हैं कि ज़ी के कुल 59 चैनलों में से करीब 15 चैनल क्षेत्रीय भाषा के चैनल हैं जो भविष्य में सामग्री क्षेत्र में आई कमी को खत्म करेंगे। जल्द ही कुछ दूसरे नए क्षेत्रीय चैनल लॉन्च किए जाएंगे जिसमें पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और भोजपुरी भाषा संबंधी मनोरंजन चैनल शामिल होंगे। उन्होंने बताया, 'हमारा मानना है कि एक सीमा से बड़े ग्राहक संबंधी सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। हम इन क्षेत्रों में भी विविधता लाना चाहते हैं और काफी कम समय में इन क्षेत्रों में अहम हिस्सेदारी प्राप्त करने की योजना पर काम कर रहे हैं।'

भोजपुरी के साथ हिंदी भाषी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में ज़ी की बाजार हिस्सेदारी 1.3 प्रतिशत रही है। वहीं, दक्षिण भारत में मनोरंजन एवं फिल्म के क्षेत्रीय कारोबार में ज़ी सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन साल में ज़ी की दक्षिण भारत के मनोरंजन बाजार में 0.8 प्रतिशत और फिल्म कारोबार में 0.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही है। बार्क के आंकड़े बताते हैं कि

ज़ी के लिए क्षेत्रीय भाषा चैनलों में मराठी चैनल ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया और कंपनी के क्षेत्रीय भाषाई कारोबार में अकेले महाराष्ट्र की 56 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। बार्क के अनुसार, मराठी टीवी कारोबार में अकेले ज़ी मराठी चैनल की 50.7 प्रतिशत हिस्सेदारी रही और दूसरे स्थान पर युवा चैनल रहा जिसकी 5.4 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ज़ी ने क्षेत्रीय भाषाई चैनलों में बढ़त बनाए रखी और स्थानीय भाषा कारोबार में ज़ी बंग्ला तथा ज़ी उड़िया की हिस्सेदारी क्रमश: 45.6 प्रतिशत तथा 41.5 प्रतिशत रही।

दक्षिण भारत के बाजारों को देखें तो ज़ी कन्नड़ 35.4 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं, दूसरे प्रमुख बाजारों जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना/आंध्र प्रदेश में ज़ी ने सन चैनल और स्टार मां चैनल के साथ अच्छा प्रदर्शन किया।

मिश्रा कहते हैं कि कंपनी इन बाजारों में दर्शक संख्या बढ़ाने और दक्षिण भारत के फिल्म बाजार में सामग्री विस्तार पर काम कर रही है।